आप सभी पाठकों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

₹ 25/-

अक्टूबर 2025

स्मार्ट सिटीज़न

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

"हिंदू एकता के नायक"

सफलता की ज्योत जलाओ, इंदिरा गैस के साथ मनाओ समृद्धि की दिवाली!

इस दिवाली, इंदिरा गैस के डीलर या डिस्ट्रिब्यूटर बनें

और भरोसेमंद ब्रांड के साथ लाभदायक व्यवसाय शुरू करें!

Toll Free: 1800-419-8757

Website: www.indiragas.com, www.indirafuel.com

REGISTRATION OPEN NOW
Visit
www.indiragas.com
and Apply Now

डीजल डिलीवरी व्यवसाय से हर महीने

₹60,000 कमाएँ!

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें :

Head Office : B- 406, 4th Floor, Sagar Tech Plaza, Andheri Kurla Road, Sakinaka Junction, Andheri East, Mumbai 400072

Corporate Office : Indira Gas And Petroleum Private Limited 502, Fifth Floor, Levana Cyber Heights, Gomti Nagar, Lucknow 226010, Up.
Contact - 0522-4233362, Email Id : Lucknow@indiragas.com

Registered Office : Unit No. Ff-30, Pearls Omaxe Tower, Nsp Delhi, India-110034, Contact - +91-7840036810Email Id : Delhi@indiragas.com

Western Corporate Office : Office No. 1019 , 10th Floor , Iconic Shyamal , Shyamal Cross Roads, 132 Feet Ring Rd, Swinagar Society, Nehru Nagar, Shyamal, Ahmedabad, 380015, Gujarat, Contact - +91-9151911191, Email Id : Ahemdabad@indiragas.com

Rajasthan Enquiry Office : 60 Feet Road, Mannaka Road, Near Adarsh Vidya Mandir, Alwar, Rajasthan

Divisional Office : 1st Floor, Sco 324-25, Sector 38-d, Sector 38, Chandigarh, 160038, Contact - +91-9151911195, Email Id : chandigarh@indiragas.com

Haryana Zonal Office : Fifth Floor, Tower 1, Dlf Corporate Greens, 515, Sector 74a, Gurugram, Haryana, 122004, Contact - 18004198757

डाक पंजीकरण संख्या/एल/स्मार्ट सिटीजन/हिन्दी मासिक पत्रिका 2025-2027

RNI No.-UPHIN/2023/87357

मासिक पत्रिका
स्मार्ट सिटीजन

वर्ष-3 अंक-4 अक्टूबर 2025

प्रधान संपादक
मनीष कुमार पाण्डेय
संपादक
अमान जाफ़री
सलाहकार संपादक
ब्रजेन्द्र कुमार सिंह
नफ़ीस जाफ़री
क़ानूनी सलाहकार
एडवोकेट स्वीटी पांडेय
(अधिवक्ता–उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच)
उप संपादक
शबाब हुसैन
महाराष्ट्र ब्यूरो
विजय यादव
लखनऊ ब्यूरो
शिवा शर्मा (संवाददाता)
संदीप मिश्रा (संवाददाता)
अमन सिंह (संवाददाता)
ग्राफ़िक डिजाइनर
मोहम्मद इरशाद खान

लखनऊ कार्यालय
विज्ञान खंड–1, छोटा भरवारा
गोमती नगर लखनऊ।
मुंबई कार्यालय
929,सर्वोदय नगर, वेस्टर्न एक्सप्रेस
हाईवे, नियर आरे सिंग्नल, आरे कालोनी,
गोरेगांव (ईस्ट), मुंबइ,महाराष्ट्र।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, रूमी काज़ी द्वारा
एन.बी. प्रिन्टर्स, मकान नंबर 85/43
आबू नगर रोड इमामगंज,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश 212601
से मुद्रित कराकर
मकान नंबर 170, महाजरी फतेहपुर,
उत्तर प्रदेश 212601
से प्रकाशित किया।
Email:-Smartcitizenftp@gmail.com
Mob. : 9451548620

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्णरूप से
पुर्नप्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है।
लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं।
उनसे संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है।
किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए
न्यायक्षेत्र फतेहपुर होगा।

इस महीने

आवरण कथा

"हिंदू एकता के नायक"
एक मुख्यमंत्री, जिसने आस्था को शासन
और राष्ट्रनिर्माण की धुरी बना दिया

पेज नं०–20–22

राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली सौ वर्ष

पेज नं०–5

किस ओर मुड़ेंगे आज़म?
सपा के पुराने शेर की नई
दहाड़ से सियासत में हलचल

पेज नं०–9

चुनाव से पहले जब कांग्रेसी नेताओं के बिगड़े बोल पार्टी को उठाना पड़ा था "बड़ा" नुक़सान

पेज नं०–15

अडाणी को क्लीन चिट मिलने के बाद क्या अब हिंडनबर्ग और राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे

पेज नं०–26–27

मनीष कुमार पाण्डेय

पाकिस्तान की नई चाल

सम्पादकीय

पाकिस्तान किस तरह से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा है, इससे जुड़े सबूत सामने आए हैं। ये सबूत ऐसे हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से डर कर आतंकवादी तंजीमें में अपने ठिकाने बदल रही हैं। जैश–ए–मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के बाद अब लश्कर ए तैयबा भी अपना प्रशिक्षण केंद्र खैबर–पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय हमलों से बचाव और निगरानी से बचना है। लश्कर ने अपना नया ठिकाना खैबर–पख्तूनख्वाह के लोअर दिर जिले के कुंबन मैदान इलाके को बनाया है। यहां लश्कर मरकज जिहाद–ए–अक्सा नाम से नया प्रशिक्षण एवं आवासीय केंद्र बना रहा है। यह जगह अफगानिस्तान सीमा से लगभग 47 किमी दूर है। सूत्रों के मुताबिक यह निर्माण कार्य जुलाई 2025 में शुरू हुआ और 22 सितंबर तक इसकी पहली मंजिल का ढांचा बनकर तैयार हो गया। यह केंद्र लश्कर की हाल ही में बनी 'जामिया अहले सुन्नत' मस्जिद के करीब खाली पड़ी लगभग 4,643 वर्ग फुट जमीन पर बनाया गया है। साफ है कि लश्कर धार्मिक संस्थानों की आड़ में आतंकी ठिकानों का निर्माण कर रहा है।

नए केंद्र का नेतृत्व नस्र जावेद को सौंपा गया है, जो 2006 हैदराबाद बम धमाके का एक मास्टरमाइंड है। फिलहाल यह लश्कर की धन–उगाही करने वाली शाखा 'खिदमत–ए–खल्क' का कामकाज संभाल रहा है। इसी को पहले फलाह–ए–इंसानियत फाउंडेशन कहा जाता था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बैन कर दिया था। साथ ही जिहाद की सैद्धांतिक शिक्षा की जिम्मेदारी मुहम्मद यासीन (उर्फ बिलाल भाई) को दी गई है। जबकि हथियार प्रशिक्षण का प्रभारी अनास उल्लाह खान को बनाया गया है। इस शिविर का स्थान जानबूझकर 'मरकज जामिया अहले सुन्नतश के पास चुना गया है ताकि आतंकवादियों की भर्ती, रसद और धार्मिक गतिविधियों की आड़ में आतंकी गतिविधियां चलाई जा सकें।

सूत्रों के अनुसार, मरकज़ जिहाद–ए–अक्सा में दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'दौरा–ए–खास' और 'दौरा–ए–लश्कर' संचालित किए जाएंगे। यह केंद्र लश्कर की 'जान–ए–फ़िदाई फ़िदायीन इकाई का स्थान लेगा। इससे पहले यह इकाई भीम्बर–बरनाला के 'मरकज अहले हदीस' से संचालित होती थी जिसे 7 मई को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया था। हालांकि सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इतनी दूर भी निशाना साधा जा सकता है।

ग़ौरतलब है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन ने भी अपने ठिकाने खैबर पख़्तूनख्वाह में शिफ्ट किए थे. लश्कर का नया ठिकाना भी इसी इलाके में होगा जिससे यह जाहिर होता है कि इसके पीछे आतंकवादी संगठनों की योजना बेहतर आपसी समन्वय रखने की है। इस पूरी मुहिम में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की प्लानिंग साफतौर पर दिखाई देती है. लश्कर 'मरकज जिहाद–ए–अक्सा' के अलावा 'मरकज–ए–खैबर गढ़ी हबीबुल्लाह' और बटरासी स्थित शिविरों का विस्तार भी कर रहा है। इसका मकसद पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में नष्ट किए गए पुराने ठिकानों के बाद आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षण आदि का धंधा फिर से शुरू किया जा सके। मरकज जिहाद–ए–अक्सा के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। आतंक का यह ठिकाना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लश्कर ने नए सिरे से आतंकवादियों की भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

प्रधान संपादक

राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली सौ वर्ष

दीपक कुमार त्यागी

डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने पावन पर्व विजयदशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना राष्ट्र, संस्कृति व समाज हित के लिए की थी। संघ स्थापना काल से लेकर के आज तक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करते हुए अपने कार्यों के दम पर करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हुए, राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से योगदान देने का कार्य निरंतर कर रहा है। हालांकि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण के दिन से ही उसके बारे में तरह–तरह का दुष्प्रचार करने की क्षणिक स्वार्थ पूरा करने वाली राजनीति की जबरदस्त ढंग से होती रही है, यह लोग ओछी राजनीति से वशीभूत होकर के राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की कोई भी भूमिका नहीं रही, आम जनमानस को ऐसा बता कर के संघ के प्रति आम जनमानस को बरगलाने का प्रयास करते हैं, जो सरासर ग़लत है।

वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र निर्माण के लिए किये गये कार्यों की लंबी फेरहिस्त देखें तो उससे यह स्पष्ट होता कि राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हमेशा अनमोल योगदान रहा है, उस योगदान की अनदेखी करना देश हित व समाज हित में उचित नहीं है। इसलिए समय रहते हम लोगों को यह समझना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का अनुशासित सांस्कृतिक संगठन है, संघ का स्वयंसेवक बिना किसी लोभ–लालच के राष्ट्र व समाज के लिए निस्वार्थ भाव से अपने तन, मन और समय को अर्पित करने का कार्य करता है। एक सच्चे स्वयंसेवक का जीवन केवल निजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अपनी सांसों को भी मातृभूमि की सेवा का साधन बना देता है, वह राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहता है।

वैसे भी किसी भी ताकतवर राष्ट्र के निर्माण के लिए अनुशासन व नैतिकता बेहद आवश्यक होती है, इन दोनों के बिना किसी भी ताकतवर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के लिए नैतिकता व अनुशासन सर्वोपरि होता है, इसलिए उसका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है।

संघ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय निर्माण की विचारधारा के दम पर ही दुनिया भर में अपनी विशेष पहचान रखता है। यह देश व दुनिया का एक ऐसा संगठन है जो अपनी विशेष कार्यशैली के दमखम पर दुनिया में सनातन धर्म–संस्कृति के रक्षक तौर पर और एक बहुत बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। संघ अपने निर्माण के सौ वर्षों के लंबे सफ़र के बाद अब अपनी कार्यशैली के बलबूते दुनिया के ताकतवर बड़े गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) में शुमार हो गया, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक फैलें हुए हैं और सबसे अहम बात यह है कि संघ दुनिया भर का एक ऐसा संगठन है, जोकि अपनी स्थापना के सौ वर्षों के बाद भी अपनी विचारधारा व उद्देश्यों से जरा भी नहीं भटका है, आज भी अपनी विचारधारा पर संघ पूरी तरह से कायम है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि संघ के राष्ट्र निर्माण व समाज के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समर्पित स्वयंसेवकों की टोली हमेशा अपना कार्य

निस्वार्थ भाव से करना जारी रखती और कभी भी श्रेय लेने तक का भी प्रयास नहीं करती है। हालांकि देश व दुनिया में जब से डिजिटल क्रांति आयी है तब से लोगों को यह पता चलने लगा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना काल के दौर से ही राष्ट्र निर्माण, एकता और सांस्कृतिक जागरण के दीप को प्रज्ज्वलित करते हुए समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने पर जोर दिया है। देश की आज़ादी के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जहां लोगों को राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत करने का कार्य बखूबी किया था, वहीं आजाद भारत में संघ ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास करते हुए एकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हुए राष्ट्र व समाज हित में निरंतर कार्य कर रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों तक में भी संघ अपनी 55 हज़ार शाखाओं व करोड़ों स्वयंसेवकों के माध्यम से पहुंच कर जनहित व राष्ट्रहित के कार्यों को निरंतर अंजाम दे रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य की बात करें तो संघ के स्वयंसेवकों ने वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की सहायता करते हुए, उन लोगों के जान–माल की सुरक्षा करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया था।

लद्दाख के जेन-जेड क्रांति से सबक सीखे भारत, अन्यथा..!

कमलेश पांडे

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। इसके बाद लेह में प्रदर्शनकारी छात्रों की सुरक्षाबलों से झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा घायल है। वहीं, प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। चूंकि यह अतिवादी कार्रवाई है। इसलिए हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं, हालात को देखते हुए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। बिना मंजूरी के रैली और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है।

बताते चलें कि लद्दाख को राज्य का दर्जा समेत कई मांगों पर सोशल ऐक्टिविस्ट सोनम वांगचुक विगत 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। लिहाजा, उनकी मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बंद बुलाया। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। जिसके बाद गत सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। इसी दौरान हिंसा हुई। सरकारी सूत्रों ने कहा कि हिंसा में राजनीति से प्रेरित साजिश की बूआ रही है।

वहीं, केंद्र सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सोनम वांगचुक के उकसाऊ बयानों से यह हिंसा भड़की है। इससे पहले वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताते हुए अनशन तोड़ दिया। उन्होंने इन घटनाओं के लिए जेन–जेड (1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी) की हताशा को जिम्मेदार ठहराया और शांति की अपील की। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों की 4 अहम मांगें हैं– लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्वोत्तर की तरह संवैधानिक सुरक्षा, करगिल, लेह की अलग–अलग लोकसभा सीट और सरकारी जॉब्स में में स्थानीय लोगों की भर्ती।

इससे स्पष्ट है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीन के हमदर्द राहुल गाँधी जो नेपाल–बंगलादेश की तरह पूरे देश में यही कुछ चाहते थे, के मनोरथ पूर्ण होने की तरफ बात बढ़ चली है। यदि शेष भारत में गृहयुद्ध भड़कता है तो इसके लिए इस देश में केवल विपक्षी दल, कथित सिविल सोसायटी और बाहरी शक्तियाँ, यथा– अमेरिकी डीप स्टेट तथा इस्लामिक अतिवादी संस्थाएं दोषी तो होंगी ही, साथ ही साथ इस बद से बदतर स्थिति के लिए कथित राष्ट्रभक्त हिंदू और सनातन धर्म प्रेमी लोगों का एक बड़ा तबका भी होगा जो उनके इशारे पर थिरकते हैं।

ऐसा इसलिए कि आप लद्दाख की इस घटना से लेकर नेपाल के हाल–फिलहाल के वाक़्ये तक इनके द्वारा लिखी व बोली गई अनाप–शनाप बातों से अंदाजा लगा सकते हैं।वास्तव में ये जाने–अनजाने में देश धर्म विरोधी तत्वों के हथियार बन रहे हैं। यह गम्भीर बात है। इससे संवैधानिक सफलता भी संदिग्ध हुई है। सच कहूं तो भारत के अतिसंवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश श्लद्दाखश से जेन–जेड क्रांति का जो आगाज दिखाई–सुनाई पड़ा है, यह हमें समय रहते ही सावधान करने के लिए काफी है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। चाहे सम्बन्धित सेना हो या सिविल व पुलिस प्रशासन, यदि उनके द्वारा अमेरिकी खुफिया इकाई सीआईए द्वारा प्रोत्साहित इस कथित जेड–जेन क्रांति को सख्ती पूर्वक नहीं कुचला गया तो उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा!

बेहतर होगा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को अविलंब कैद करके उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उनके कुकर्मों से धन–जन की हानि हुई है, अन्यथा भारतीय लोकतंत्र में भी एक गलत ट्रेंड स्थापित हो जाएगा। एशियाई लोकतंत्र की सफलता पर सवाल उठेंगे। ऐसा इसलिए कि पश्चिमी लोकतंत्र खूनी लोकतंत्र है, पक्षपाती डेमोक्रेसी है। जिसका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक जनभावना मजबूत करना नहीं, बल्कि अपने आर्थिक व साम्राज्यवादी लाभ के लिए दुनिया में कठपुतली सरकार कायम करना है। यही वजह है कि जेन–जेड जैसी कथित क्रांति से हो रहे सत्ता परिवर्तन और बन रही कठपुतली सरकारों को दुनियावी लोकतंत्र की सफलता के लिहाज से उचित नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लद्दाख घटनाक्रम के बाद भारत को ठोस और प्रभावी कदम उठाने ही होंगे और

इससे अपने पड़ोस को भी लाभान्वित करने की सद्भावना रखनी होगी।

कहना न होगा कि 2014 की सनातन युवा क्रांति के बाद बनी भाजपा नीत मोदी सरकार की सफलता से ही भारत, अमेरिका–चीन और अरब देशों के निशाने पर है। इसलिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल आदि में जो जेन–जेड क्रांति हुई, उसका मकसद भारतीय राजनेताओं और सेना के धैर्य की परीक्षा लेना था। जब हम लोकतंत्र की पैरोकारी में मजबूती पूर्वक विफल रहे तो लद्दाख जेन–जेड क्रांति हमें मुबारक कर दिया गया। सवाल है कि यह भी प्रयोग केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू–कश्मीर के बजाय बौद्ध धर्म बहुल लद्दाख में करवाया गया ताकि बौद्धों के प्रति हिंदुओं के मन में नफरत पैदा हो और चीन–भारत व तिब्बत–भारत के रिश्तों में पलीता लगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ होता तो बेहतर होता। लेकिन चरमपंथियों और हिंसकों को कुचलने के बजाय स्थानीय सेना व प्रशासन द्वारा ऐसे अराजक तत्वों से बात करने से समकालीन लोकतंत्र के प्रति गलत संदेश गया है।

लिहाजा, अविलंब इसकी भरपाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, रूस और चीन आदि के साथ मिलकर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा असहयोग मिलने पर भारत की सेना को ही इन पर आक्रमण करके इन्हें भारतीय भूभाग में मिला लेना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिमी देशों व ब्रिक्स देशों जैसे लोकतंत्र के कथित दरिंदों को ग्लोबल साउथ के समक्ष बेनकाब करने की स्पष्ट रणनीति अख्तियार करनी चाहिए। कहने का तातपर्य यह कि विधि के शासन को बहाल करने के लिए भारत व उसके पड़ोसी देशों की सेना को आपसी सांठगांठ करके व स्थानीय सिविल व पुलिस प्रशासन को भरोसे में लेकर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में हर तरह की कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना चाहिए और किसी तरह के कत्लेआम से गुरेज नहीं करना चाहिए। अन्यथा भारत विकास और सुशासन की रेस में पिछड़ जाएगा।

समकालीन जेन–जेड की हिंसक प्रवृति को देखते हुए लोगों को आशंका है कि जी–7 और ब्रिक्स के कतिपय चतुर सुजान देश यही अराजकता चाहते हैं, ताकि उनके गोला–बारूद की खपत बढ़े। इसी की आड़ लेकर वे दुनियावी प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें। इसलिए भारत को अविलंब जिला स्तर पर अपनी तैयारी को धार दी जानी चाहिए, ताकि हिंसक व अराजक तत्वों को उनकी औकात में रखा जा सके। अन्यथा यह श्खूनी लोकतंत्रश भविष्य में अमेरिकी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। बहरहाल ये अराजकता पैदा करके हथियार बेचेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप भी अरब व खाड़ी देशों की तरह झुलसता रहेगा।

बताते चलें कि कथित पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख में चल रहा प्रदर्शन जिस प्रकार से हिंसक हो गया और भाजपा के कार्यालय तक को निशाना बनाया गया, उसमें भाड़े के उत्पाती शामिल नहीं हैं तो क्या हैं? यह ठीक है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुआई में लंबे वक्त से यह मांग उठायी जा रही है और इसे लेकर केंद्र से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन, इस दौरान इस सोच का हिंसा का हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक दोनों है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पूरे देश में एक सही संदेश जाए।

यह ठीक है कि सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35–ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू–कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा है। फिर भी लेह में हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे विदेशी ताकतों के हाथ की पड़ताल और जम्मू–कश्मीर सरकार की परोक्ष भूमिका की जांच होनी चाहिए।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से आंदोलनरत रहे हैं। पिछले साल मार्च में भी वह 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बाद दिल्ली तक पदयात्रा निकाली। इस समय भी उन्होंने 15 दिनों का अनशन शुरू किया था, लेकिन एक दिन पहले दो लोगों की तबीयत बिगड़ी और हालात काबू से बाहर हो गए। यह हिंसा कतई उचित नहीं है।

चूंकि लेह में हुए प्रदर्शन को जेन–जेड का आंदोलन कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले यही पीढ़ी नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। लेकिन, नेपाल और लद्दाख की तुलना कतई नहीं की जा सकती है। और न ही हिंसा को किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है। वैसे भी सोनम वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। यहां तक कि सरकार से मतभेद होने पर भी उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा है। लिहाजा, उनके समर्थन में खड़े युवाओं को इसे समझना चाहिए। क्योंकि विदेशी शह प्राप्त हिंसा से उनकी समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी

ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? भारत के प्रगतिशील लोगों की राय है कि इसके लिए लद्दाख के लोगों की चिंता पर संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। चूंकि छठी अनुसूची, स्वायत्तता और स्वशासन के कुछ विशेष अधिकार देती है। इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की तरह ही लद्दाख को भी इस सूची के तहत सुरक्षित किये जाने की पहल अविलंब की जानी चाहिए।

बताया गया है कि केंद्र सरकार और आंदोलन में शामिल लेह एपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच आगामी 6 अक्टूबर को बातचीत प्रस्तावित है। इसलिए लोगों में यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि फैसलों में लद्दाख के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका पारदर्शिता है। वहीं, जनता को भी समझना होगा कि सरकार के लिए हर मांग मानना और तुरंत मानना संभव नहीं होता है। इसके लिए भी कमेटी गठित करनी पड़ती है।

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया अहम फ़ैसला तिहाड़ जेल से हटेगी अफ़ज़ल गुरू की कब्र?

एडवोकेट स्वीटी पांडेय
अधिवक्ता (उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें तिहाड़ जेल परिसर से आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। दोनों आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई थी और जेल परिसर में फांसी दी गई थी।

उच्च न्यायालय के संकेत को भांपते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि याचिका वापस लेने और इसे कुछ आंकड़ों के साथ इसे पुनः दाखिल करने की अनुमति दी जाए।. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और इसे "वापस लिया गया मानते हुए खारिज" कर दिया। पीठ ने कहा, ''किसी जनहित याचिका में राहत पाने के लिए अदालत का रुख करने के लिए, आपको हमें संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों या वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाना होगा। कोई भी कानून या नियम जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने पर रोक नहीं लगाता है।

कब्रों का निर्माण, उनका निरंतर अस्तित्व अवैध और जनहित के विरुद्धः– जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि अगर आवश्यक हो तो शव को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि 'आतंकवाद का महिमामंडन और जेल परिसर का दुरुपयोग रोका जा सके। 'विश्व वैदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित जेल के अंदर इन कब्रों का निर्माण और उनका निरंतर अस्तित्व 'अवैध, असंवैधानिक और जनहित के विरुद्ध है।

तिहाड़ केंद्रीय जेल को 'कट्टरपंथी तीर्थस्थलश में बदल दियाः– याचिका में आरोप लगाया गया कि इन कब्रों की मौजूदगी ने तिहाड़ केंद्रीय जेल को 'कट्टरपंथी तीर्थस्थल में बदल दिया है, जहां चरमपंथी तत्व दोषी ठहराए गए आतंकवादियों का महिमामंडन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसमें कहा गया, "यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि भारत के संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन करते हुए आतंकवाद को भी सही ठहराता है।"

याचिका में दावा किया गया कि जेल के अंदर इन कब्रों का होना 'दिल्ली कारागार नियमावली, 2018श के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था, "इसलिए याचिकाकर्ता इस न्यायालय से शीघ्र हस्तक्षेप की गुहार करते हैं कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे तिहाड़ जेल से उक्त कब्रों को हटा कर उन्हें सुरक्षित और गुप्त स्थान पर पुनः स्थापित करें, जैसा कि अजमल कसाब और याकूब मेमन जैसे फांसी पाए आतंकवादियों के मामलों में स्थापित राज्य प्रथा के अनुसार हर सावधानी बरती गई थी, ताकि उनकी महिमामंडन से बचा जा सके। याचिका में कहा गया है कि भट्ट और गुरु दोनों ने 'चरमपंथी जिहादी विचारधारा के प्रभाव में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया, जिससे भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को गंभीर खतरा है। भट्ट को 1984 में और अफजल गुरु को फरवरी 2013 में फांसी दी गई थी।

किस ओर मुड़ेंगे आज़म ?

सपा के पुराने शेर की नई दहाड़ से सियासत में हलचल

मनीष कुमार पाण्डेय

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल है– वजह हैं आज़म खान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी और रामपुर की राजनीति का चेहरा माने जाने वाले आज़म खान जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। उनके बयान, उनके हावभाव और उनके रुख में बार–बार दिखता परिवर्तन अब राजनीति के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या आज़म खान अब सपा से किनारा करेंगे या फिर किसी नए समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं?

आज़म खान का राजनीतिक सफर समाजवादी आंदोलन की कहानी का अहम अध्याय रहा है। मुलायम सिंह यादव के साथ शुरू हुआ यह रिश्ता तीन दशकों से भी ज़्यादा समय तक उतार–चढ़ावों से गुज़रा। रामपुर के इस सियासी किले में आज़म खान ने अपनी मज़बूत पकड़ बनाई, मुस्लिम समाज में उनका प्रभाव एक समय अपार था। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के नये दौर में वह धीरे–धीरे हाशिये पर जाते दिखे। फिर आई जेल की सजा कई मामलों में फंसे, राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, और अंततः लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आए तो बदल चुका था बहुत कुछ–सपा की राजनीति, नेतृत्व का ढांचा और जनता की प्राथमिकताएँ।

अखिलेश यादव ने जेल से छूटने के बाद जब आज़म खान से मुलाकात की, तो सियासी गलियारों में इसे "पुरानी दोस्ती की मरम्मत" के तौर पर देखा गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आज़म खान के बयानों ने पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी। कभी वह सपा की "बदलती सोच" पर तंज कसते हैं, तो कभी इशारों–इशारों में यह कहते हैं कि "हमने घर बनाया था, अब उसमें हमें ही जगह नहीं।" यह बयानबाज़ी न सिर्फ़ अखिलेश–अज़म रिश्तों की दूरी दिखाती है, बल्कि सपा के भीतर पुराने और नये नेतृत्व के बीच अदृश्य टकराव की झलक भी देती है।

सियासी सूत्रों का कहना है कि आज़म खान अब अपनी भूमिका को "पुनर्परिभाषित" करने में जुटे हैं। वह यह जताना चाहते हैं कि उनकी उपेक्षा कर सपा मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट नहीं रख सकती। हाल के उनके

आज़म खान की सियासी पहचान सपा के संस्थापक सदस्य और मुलायम सिंह के सबसे करीबी नेताओं में से एक। रामपुर से लगातार विधायक और सांसद रहे। सपा सरकारों में शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलों और नगर विकास जैसे अहम मंत्रालय संभाले। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर विवादों में घिरे रहे। मुस्लिम राजनीति के सबसे मुखर चेहरों में गिने जाते हैं।

बयानों में भाजपा की नीतियों की अप्रत्यक्ष तारीफ़ और सपा पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने कई तरह की अटकलों को हवा दी है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि आज़म फिलहाल किसी नई पार्टी या गठबंधन की ओर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अपने प्रभाव का प्रदर्शन करके सपा में अपनी शर्तों पर जगह बनाना चाहेंगे।

रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी आज़म खान का प्रभाव ज्यों का त्यों है। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह उनका स्वागत हुआ, उसने यह साबित किया कि उनकी जनाधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मुस्लिम समाज के बीच उनकी छवि अब भी एक 'प्रतिरोध के प्रतीक' की है, जिसने सत्ता के दबाव के बावजूद झुकने से इंकार किया। यही छवि उन्हें अब भी एक बड़ा सियासी पूंजी देती है। समाजवादी पार्टी के लिए यह वक्त बेहद नाजुक है। एक तरफ पार्टी भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बात कर रही है, दूसरी तरफ़ अपने पुराने स्तंभों के असंतोष से जूझ रही है। अगर आज़म खान सपा से पूरी तरह किनारा कर लेते हैं, तो इसका असर सिर्फ़ एक सीट या जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में पार्टी की साख पर पड़ सकता है। सपा नेतृत्व को समझना होगा कि आज़म खान सिर्फ़ एक नेता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतीक हैं कृ जो सामाजिक न्याय और मुस्लिम सशक्तिकरण की राजनीति के केंद्र में रहे हैं।

आज़म खान आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ से उनकी हर दिशा में बढ़ाई गई एक–एक चाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर सकती है। सवाल अब यह नहीं कि आज़म खान किस ओर मुड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी उनके बिना आगे बढ़ने की ताकत रखती है? जवाब फिलहाल हवा में तैर रहा है, लेकिन इतना तय है कि जब भी आज़म बोलेंगे, राजनीति की लहरें एक बार फिर तेज़ होंगी।

अखिलेश की चुनौती नई पीढ़ी की राजनीति में आज़म जैसे नेताओं के लिए जगह सीमित। सपा की मुस्लिम राजनीति पर अब नए चेहरे हावी। आज़म के असंतोष से रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिम यूपी में सपा की मुस्लिम पकड़ कमजोर हो सकती है। पार्टी नेतृत्व आज़म को सम्मान देने और अनुशासन में रखने के बीच संतुलन खोज रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

1–सपा में वापसी का सम्मानजनक रास्ता–

अखिलेश से रिश्ते सुधरें तो वे पार्टी में "मार्गदर्शक" भूमिका निभा सकते हैं।

2. नया मोर्चा या स्वतंत्र स्वर–

वे किसी छोटे क्षेत्रीय गठबंधन या मुस्लिम नेतृत्व वाले मोर्चे से जुड़ सकते हैं।

3.आज़म अपने प्रभाव का उपयोग सपा के भीतर शक्ति–संतुलन के लिए कर सकते हैं, बिना खुलकर किसी दिशा में जाने के।

राजद प्रवक्ताओं का टीवी डिबेट्स में व्यवहार- लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल

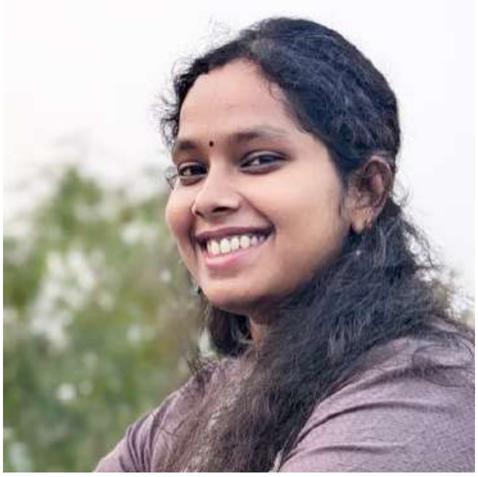

आशीष कुमार अंशु

भारत में हाल के दिनों में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रवक्ताओं–कंचना यादव, सारिका पासवान और प्रियंका भारती–के टीवी डिबेट्स में अभद्र व्यवहार और अपशब्दों से भरे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन प्रवक्ताओं का आचरण न केवल राजनीतिक चर्चा के स्तर को नीचे लाता है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। न्यूज चौनलों पर होने वाली पैनल चर्चाओं में ये प्रवक्ता तथ्यों और तर्कों के बजाय व्यक्तिगत हमलों, अपशब्दों और प्रोपेगेंडा का सहारा लेती नजर आ रही हैं। इस तरह की हरकतों की कड़ी आलोचना हो रही है, और जनता के बीच इनके प्रति गुस्सा और निराशा साफ देखी जा सकती है।

इन वायरल वीडियो में कंचना यादव, सारिका पासवान और प्रियंका भारती का अन्य पैनलिस्टों के साथ व्यवहार निंदनीय रहा है। ये प्रवक्ता अक्सर चर्चा के दौरान विषय से भटककर व्यक्तिगत टिप्पणियां करती हैं और विरोधी पक्ष के तर्कों को सुनने की बजाय चीख–चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक प्रमुख न्यूज चौनल पर आयोजित डिबेट में कंचना यादव ने एक पैनलिस्ट को अपशब्द कहते हुए उनकी योग्यता पर सवाल उठाया। यह व्यवहार न केवल असभ्य था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे तथ्यपरक चर्चा में हिस्सा लेने के बजाय माहौल को विषाक्त करने में अधिक रुचि रखती हैं। इसी तरह, सारिका पासवान ने एक अन्य चर्चा में बिना किसी तथ्य के विपक्षी दलों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, जिसका कोई ठोस आधार नहीं था। प्रियंका भारती ने भी एक डिबेट में तर्कों को नजरअंदाज करते हुए भावनात्मक प्रोपेगेंडा और महिला व पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की, जो उनकी कमजोर तैयारी को उजागर करता है।

यह विशेष रूप से शर्मनाक है कि ये प्रवक्ता अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बार–बार महिला और पिछड़ा होने का कार्ड खेलती हैं। यह रणनीति न केवल पुरानी और घिसी–पिटी हो चुकी है, बल्कि यह समाज के उन लोगों का भी अपमान करती है जो वास्तव में अपने समुदाय के लिए संघर्ष करते हैं। अगर इन प्रवक्ताओं को वंचित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेनी है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता डॉ. गुरु पासवान को देखना चाहिए। डॉ. पासवान, जो स्वयं एक वंचित समाज से आते हैं, अपनी हर बात को तथ्यों और तर्कों के साथ पेश करते हैं। वह किसी भी प्रश्न से पीछे नहीं हटते और न ही व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते। उनकी पढ़ाई–लिखाई, गहन विषय–ज्ञान और शालीनता उन्हें एक प्रभावी वक्ता बनाती है। उनकी तार्किक क्षमता और व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक पृष्ठभूमि कोई बहाना नहीं होनी चाहिए; मेहनत, ज्ञान और सभ्यता ही असली ताकत हैं। क्या राजद की प्रवक्ताएं उनसे कुछ नहीं सीख सकतीं?

राजद प्रवक्ताओं की सबसे बड़ी कमी उनकी तथ्यहीनता और तैयारी की कमी है। जब उनसे तथ्य और आंकड़े मांगे जाते हैं, तो वे या तो विषय बदल देती हैं या फिर चीख–चिल्लाकर माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, एक हालिया डिबेट में जब कंचना यादव से बिहार में राजद शासन के दौरान शिक्षा और रोजगार के आंकड़ों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय विपक्षी पैनलिस्ट पर

> *"यह रणनीति न केवल पुरानी और घिसी–पिटी हो चुकी है, बल्कि यह समाज के उन लोगों का भी अपमान करती है जो वास्तव में अपने समुदाय के लिए संघर्ष करते हैं। अगर इन प्रवक्ताओं को वंचित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेनी है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता डॉ. गुरु पासवान को देखना चाहिए। डॉ. पासवान, जो स्वयं एक वंचित समाज से आते हैं, अपनी हर बात को तथ्यों और तर्कों के साथ पेश करते हैं। वह किसी भी प्रश्न से पीछे नहीं हटते और न ही व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते। उनकी पढ़ाई–लिखाई, गहन विषय–ज्ञान और शालीनता उन्हें एक प्रभावी वक्ता बनाती है। उनकी तार्किक क्षमता और व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक पृष्ठभूमि कोई बहाना नहीं होनी चाहिए; मेहनत, ज्ञान और सभ्यता ही असली ताकत हैं। क्या राजद की प्रवक्ताएं उनसे कुछ नहीं सीख सकतीं?*

व्यक्तिगत टिप्पणी की। यह व्यवहार न केवल उनकी अक्षमता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे जनता के असल मुद्दों से कितनी दूर हैं। इसी तरह, सारिका पासवान ने एक अन्य चर्चा में बिहार में अपराध दर के आंकड़ों पर सवाल उठाए जाने पर तथ्यों के बजाय विपक्षी दलों पर अनर्गल आरोप लगाए। प्रियंका भारती भी अक्सर तथ्यों के अभाव में भावनात्मक अपील का सहारा लेती हैं, जो उनकी कमजोर तैयारी को और उजागर करता है।

सोशल मीडिया पर इन वीडियो को देखकर जनता का गुस्सा साफ झलकता है। लोग इन प्रवक्ताओं की तुलना उन नेताओं और प्रवक्ताओं से कर रहे हैं जो तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे मंचों पर यूजर्स ने इन प्रवक्ताओं के व्यवहार को ष्शर्मनाकष और ष्असभ्यष करार दिया है। एक यूजर ने लिखा, ष्राजद की प्रवक्ताएं तथ्यों के बजाय चीख–चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। यह राजनीति नहीं, नौटंकी है।ष एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया, ष्क्या राजद के पास ऐसे प्रवक्ता नहीं हैं जो तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रख सकें?ष यह जनता की निराशा और गुस्से का स्पष्ट संकेत है।

यह समय है कि राजद अपनी प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित करे और उन्हें समझाए कि राजनीतिक चर्चा का मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं, बल्कि जनता को सच्चाई से अवगत कराना है। इन प्रवक्ताओं को यह समझना होगा कि अपशब्द और अभद्रता उनकी कमजोरियों को और उजागर करती है। अगर वे डॉ. गुरु पासवान जैसे प्रवक्ताओं से प्रेरणा लें, तो शायद वे अपनी विश्वसनीयता को बचा सकें। डॉ. पासवान का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे न केवल अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का सकारात्मक उपयोग करते हैं, बल्कि अपनी तार्किक क्षमता और गहन ज्ञान के साथ हर चर्चा में प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी शालीनता और तथ्यपरकता राजद की प्रवक्ताओं के लिए एक सबक हो सकती है।

राजद को यह भी समझना होगा कि टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया के इस युग में जनता की नजरें हर बात पर हैं। लोग अब उन नेताओं और प्रवक्ताओं को महत्व देते हैं जो तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। अगर राजद अपनी छवि को सुधारना चाहता है, तो उसे अपनी प्रवक्ताओं को तथ्यपरक और सभ्य व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए पार्टी को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए–

प्रशिक्षण और कार्यशालाएं:– राजद को अपने प्रवक्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिसमें उन्हें तथ्यपरक चर्चा, डिबेट की कला और शालीनता सिखाई जाए।

तथ्यों पर जोरः– प्रवक्ताओं को हर चर्चा के लिए अच्छी तरह तैयार करना चाहिए, जिसमें आंकड़े, तथ्य और नीतिगत जानकारी शामिल हो। इससे वे व्यक्तिगत हमलों और अपशब्दों से बच सकेंगी।

सभ्यता और नैतिकताः– प्रवक्ताओं को यह समझाना होगा कि अपशब्द और अभद्रता उनकी विश्वसनीयता को कम करती है। सभ्य और तार्किक व्यवहार ही जनता का विश्वास जीत सकता है।

सकारात्मक प्रेरणाः– पार्टी को डॉ. गुरु पासवान जैसे प्रवक्ताओं के उदाहरण को सामने रखना चाहिए, जो अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर सम्मान अर्जित करते हैं।

अंत में, राजद को अपनी प्रवक्ताओं की इस तरह की हरकतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जनता अब ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी जो तथ्यों के बजाय शोर–शराबे और अपशब्दों पर टिकी हो। इन प्रवक्ताओं को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा और राजनीतिक चर्चा को एक सभ्य और तार्किक स्तर पर लाना होगा। अगर राजद इस दिशा में कदम नहीं उठाता, तो उसकी छवि को और नुकसान होने का खतरा है। यह समय है कि पार्टी अपने प्रवक्ताओं को न केवल प्रशिक्षित करे, बल्कि उन्हें यह भी समझाए कि राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा करना है, न कि टीवी पर नौटंकी करना। भारतीय लोकतंत्र में सभ्य और तथ्यपरक चर्चा की जरूरत है, और राजद को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

लखनऊ की रैली- मायावती की चुप्पी टूटी, बसपा की गूंज लौटी
एक दशक बाद भी बहनजी का असर बरकरार

निमिष दुबे

प्रराजनीति में अक्सर कहा जाता है कि "मौन भी एक बयान होता है।" उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ वर्षों से इसी मौन की राजनीति कर रही थीं। लेकिन लखनऊ की कांशीराम स्मारक रैली ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। भोर से उमड़ी भीड़, मंच पर अनुशासित रचना और मायावती का संयमित किंतु पैना भाषण कृ सब मिलकर यह संदेश दे गए कि बसपा भले सत्ता से बाहर हो, पर अब भी राजनीतिक परिदृश्य से बाहर नहीं हुई है।

स्मारक से संदेश तक:– कांशीराम स्मारक पर हुई इस महारैली ने प्रतीकात्मक राजनीति का गहरा प्रभाव छोड़ा। सुबह चार बजे से ही कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ना, गांवों से निकलती बसों का लखनऊ की ओर बढ़ना, और मायावती के भाषण के दौरान छाई हुई खामोशी यह सब बता रही थी कि दलित–बहुजन समाज अब भी उस एक चेहरे पर भरोसा करता है जिसने उन्हें सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ाईं।

यह सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं थी-यह शक्ति दर्शन था

रैली के मंच से मायावती ने याद दिलाया कि बसपा का अस्तित्व किसी गठबंधन की दया पर नहीं टिका है वह खुद एक विचार है, जो सत्ता में रहे या विपक्ष में, जनचेतना में स्थायी है।

मायावती का भाषण- सपा पर तंज, भाजपा पर सहजता

मायावती ने अपने भाषण में तीन स्पष्ट संकेत दिए। पहला, सपा पर तीखा प्रहार। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़े–दलित–अल्पसंख्यक) नारे को "सिर्फ चुनावी नाटक" बताया। उनका कहना था कि सपा ने हमेशा बहुजन वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, प्रतिनिधित्व की तरह नहीं। यह तंज केवल सपा पर नहीं, बल्कि उस समूची विपक्षी राजनीति पर था जो दलितों की पीड़ा को "संविधान की भाषा" में सजाकर रखती है, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती।

दूसरा, भाजपा के प्रति अप्रत्याशित नरमी। मायावती ने कांशीराम स्मारक की मरम्मत और रखरखाव के लिए योगी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि "जो सरकार बहुजन प्रतीकों का सम्मान करती है, उसे धन्यवाद देना गलत नहीं है।" यह वाक्य छोटा था, लेकिन राजनीति में इसका अर्थ बहुत बड़ा निकला। यह वक्तव्य न सिर्फ भाजपा के लिए प्रशंसा था, बल्कि यह भी संदेश था कि बसपा किसी एक खेमे में बंद नहीं है; वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी जगह तय करती है।

तीसरा, संविधान की पुर्नपाठ की अपील। मायावती ने कहा कि जो लोग संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, वे पहले उसका पालन करना सीखें। उनका यह निशाना अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की ओर था, जिसने हमेशा "संविधान बचाओ" के नारे दिए, पर उसके मूल भाव सामाजिक न्याय और समान अवसर पर मौन साधा।

रैली का दृश्य किसी चुनावी सभा से बड़ा था।

अख़बारों ने लिखा कि लाखों कार्यकर्ता पहुंचे; कुछ रिपोर्टों ने पाँच लाख का आंकड़ा बताया। पर असल मायने सिर्फ संख्या में नहीं, उस शांति और अनुशासन में थे जिससे यह भीड़ बैठी थी। यह वही संगठनात्मक संस्कृति है जो बसपा को बाकी दलों से अलग बनाती है। कोई नारेबाज़ी नहीं, कोई अनियंत्रित व्यवहार नहीं कृ बस प्रतीक, अनुशासन और निष्ठा। इस भीड़ ने यह साबित किया कि बसपा का जमीनी ढाँचा अभी जर्जर नहीं हुआ है। वह मौन में रहा, लेकिन खत्म नहीं हुआ।

सत्ता से बाहर, लेकिन असर से नहीं

पिछले एक दशक से बसपा सत्ता से बाहर है। न तो दिल्ली में उसका प्रतिनिधित्व है, न लखनऊ में कोई शक्ति–स्थान। फिर भी, यह रैली दिखाती है कि बसपा का प्रभाव सिर्फ विधानसभाओं की सीटों में नहीं मापा जा सकता। बसपा के पास अब भी एक ऐसा सामाजिक ताना–बाना है जो किसी नारे या गठबंधन पर निर्भर नहीं। दलित–पिछड़े, खासतौर से ग्रामीण समाज, अब भी मायावती को "अपनी नेता" मानते हैं। भले वे कभी–कभी भाजपा की योजनाओं का लाभ ले रहे हों या सपा–कांग्रेस के वादों की तरफ झुके हों, लेकिन जब पहचान की बात आती है, तो "बहनजी" नाम अब भी आदर से लिया जाता है। रैली का एक दिलचस्प पहलू भाजपा के प्रति मायावती की संतुलित भाषा रही। उन्होंने सरकार के कामों की सराहना की, लेकिन समर्थन का सीधा संकेत नहीं दिया। राजनीति में इसे "सॉफ्ट अप्रोच" कहा जा सकता है कि न विरोध में, न साथ में। यह शायद मायावती की सबसे पुरानी रणनीति है कि जब विपक्ष एकतरफा आक्रामक हो, तो वह खुद को अलग रखकर "निर्णायक" बन जाती हैं। इस बार भी उन्होंने वही रास्ता चुना। यह भाजपा के लिए एक राजनीतिक अवसर है और सपा–कांग्रेस के लिए एक चिंता।

विपक्ष की बेचैनी और बयानबाज़ी

सपा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि "भाजपा और बसपा का छुपा गठबंधन अब खुलकर सामने है।" कांग्रेस ने इसे "भाजपा प्रायोजित रैली" कहा। पर जो लोग मैदान में थे, वे जानते थे कि यह रैली किसी सौदेबाज़ी का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्जीवन की शुरुआत थी। दरअसल विपक्ष की बेचौनी इसलिए भी है कि दलित–बहुजन मतदाता अब तय नहीं हैं कि वे किस ओर जाएँ। मायावती की एक रैली ही विपक्ष के समीकरण बिगाड़ सकती है। यह वही स्थिति है जो 2007 में थी, जब सबने बसपा को "कमज़ोर" कहा था और परिणाम ने सबको चौंका दिया था। लखनऊ की यह सभा कई स्तरों पर मायने रखती है।

संविधान और स्वाभिमान का संदेश

मायावती ने दलित समाज को यह याद दिलाया कि संविधान उनका सुरक्षा कवच है, किसी पार्टी का उपहार नहीं।

राजनीतिक पुनर्स्थापन

यह रैली बसपा को फिर एक "सीरियस खिलाड़ी" के रूप में पेश करती है, जो सिर्फ वोट बाँटने के लिए नहीं, बल्कि शासन के लिए तैयार है। भाजपा और सपा के बीच का सीधा संघर्ष अब तीसरे कोण से प्रभावित होगा। बसपा वह कोण है जो हर चुनाव में परिणाम पलट सकता है। आने वाले चुनाव बसपा के लिए निर्णायक होंगे। मायावती जानती हैं कि रैलियाँ भरोसा तो जगा सकती हैं, पर वोट में बदलने के लिए संगठन को बूथ–स्तर तक तैयार करना होगा। युवा चेहरे जैसे आकाश आनंद और आनंद कुमार इस रणनीति के केंद्र में हैं। बसपा अब "एक चेहरे की पार्टी" से आगे बढ़कर "संगठन की पार्टी" बनना चाहती है।

हालांकि चुनौतियाँ भी कम नहीं

दलित वोटों का नया बँटवारा, भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव, और सपा का पिछड़ा वर्ग पर पकड़। इन सबके बीच बसपा को अपनी पुरानी बहुजन प्लस सर्वजन की नीति को नए रूप में पेश करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह रैली 2027 के लिए बसपा की औपचारिक पारी की शुरुआत है। मायावती ने यह साबित किया कि वह अब भी "निर्णायक नेता" हैं, न कि राजनीतिक इतिहास का हिस्सा। उनकी राजनीतिक शैली पुराने दौर की है कृ गंभीर, सीमित शब्दों में अर्थपूर्ण प्रहार। पर यही संयम उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। भाजपा और सपा के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में बसपा फिर से "संतुलन की शक्ति" बनकर उभर सकती है। अगर मायावती ने अपने संगठन को सक्रिय रखा, और सामाजिक न्याय के साथ विकास की नई परिभाषा दी। तो यह रैली आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कही जाएगी।

लखनऊ की यह रैली केवल बसपा की सभा नहीं थी

यह एक याद थी, एक दावा था, और शायद एक भविष्य की घोषणा भी। मायावती ने किसी पर निर्भर हुए बिना यह साबित किया कि राजनीति में मौन से भी पुनर्जन्म संभव है। सत्ता से बाहर रहते हुए भी उनका असर कायम है, और यही असर उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर त्रिकोणीय बना सकता है।

बहुजन आंदोलन की यह रैली शायद इतिहास दोहरा रही है

जब सबने कहा था कि बसपा खत्म हो गई है, तब भी बहनजी ने मुस्कुराकर कहा था, "अबकी बार, हमारी बारी।"

चुनाव से पहले जब कांग्रेसी नेताओं के बिगड़े बोल पार्टी को उठाना पड़ा था "बड़ा" नुकसान

फरीद वारसी

सत्ता के चकाचौंध वाले गलियारों से लेकर भारतीय राजनीति का मैदान हमेशा से ही एक ऐसा युद्धक्षेत्र रहा है, जहां अपने विरोधियों पर भारी दिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हर शब्द कुल्हाडी के उस वार की तरह होता है, जो लक्ष्य साधने के बजाय कभी–कभी खुद के पांव पर पड़ जाता है। कांग्रेस पार्टी, जो आजकल अपने ही नेताओं के सेल्फ गोल से हारती नजर आती है। दरअसल ये वे नेता हैं, जो पार्टी के शुभचिंतक तो जरूर हैं, लेकिन उनके बयान कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गए। कांग्रेसियों के ये बयान सुनते ही विपक्षी दल मौका लपक लेते हैं और उन्हें ऐसा भुनाते हैं कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। मणिशंकर अय्यर से लेकर सैम पित्रोदा तक, ये नाम कांग्रेस के लिए एक ऐसा दर्द हैं, जो चुनावी मौसम में हर बार उभर आता है। आइए, कुछ ऐसे विवादास्पद बयानों के बारे में जानें, जहां बयानबाजी ने चुनावी हार को न केवल गहरा किया, बल्कि पार्टी को लंबे समय तक बदनाम भी कर दिया।

मणिशंकर अय्यर का पहला सेल्फ गोलः– यह कहानी शुरू होती है 2014 के लोकसभा चुनावों से, जब भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का सूरज की तरह उदय हो रहा था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी, अपनी चायवाली पृष्ठभूमि को एक ताकत और पहचान बना चुके थे। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को यह पसंद न आया। बस फिर क्या था एक रैली में अय्यर ने इसी बात पर चुटकी ली, तब उन्होंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वे चाय बेचने आ सकते हैं, मयूर भवन में चाय स्टॉल खोल सकते हैं। यह बयान जैसे आग में घी का काम कर गया। मोदी ने इसे पकड़ लिया और चाय पे चर्चा अभियान चला दिया। अचानक, चायवाला एक राजनीतिक ब्रांड बन गया, जो एलीट कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि इस बयान ने मोदी को आम आदमी का पर्याय बना दिया। हालांकि पार्टी ने तुरंत अय्यर से दूरी बना ली थीं। लेकिन तब तक कांग्रेस को काफी नुकसान हो चुका था।

अय्यर का दूसरा बयानः– 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में अय्यर फिर मैदान में उतरे, जहां भारतीय जनता में

एंटी–इनकंबेंसी, पाटीदार आंदोलन और दलित विद्रोह के बीच मोदी घरेलू मैदान बचाने की कोशिश में लगे थे, तभी एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी को फिर से अमर्यादित शब्द कहे। तब उनका ये बयान गुजराती अस्मिता को छू गया। इस बयान पर भी कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई। तब बीजेपी ने गुजरात की जनता से अपमान का बदला लेने को कहा. तब भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जीतीं, जबकि 2012 में 115 थीं, लेकिन कांग्रेस को महज 77 मिलीं। तब भी विश्लेषकों ने कहा कि अय्यर के बयान ने बीजेपी का गुजराती गौरव का मुद्दा ज्यादा हावी कर दिया, जिससे वे बच निकले।

सैम पित्रोदा का 2019 का तूफानः–

अब कहानी का टर्न लेते हैं सैम पित्रोदा की ओर, जो राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं और गांधी परिवार के करीबियों में से एक है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा, हुआ तो हुआ। अब क्या? बताओ उन्होंने पांच साल में क्या किया? उनके इस बयान ने सिखों के वर्षो पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बीजेपी भला ये मौका कहां चूकने वाली थी, उसने इसे कांग्रेस की अहंकारी मानसिकता का प्रतीक बना दिया। पंजाब में कांग्रेस की सहयोगी अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा। हालांकि कांग्रेस इस बयान को निजी बताकर उनके इस बयान से किनारा करती रही, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

रंगभेद से पाकिस्तान तक पित्रोदा का 2024 का डबल ब्लोः– साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पित्रोदा ने दो सेल्फ गोल दागे. पहले, उन्होंने भारत की विविधता बताते हुए कहा, पूर्व के लोग चीनी जैसे, दक्षिण के अफ्रीकी जैसे, उत्तर के अरब जैसे दिखते हैं। बीजेपी ने इसे नस्लवादी करार दिया. चुनाव के बीच में ये बयान भाजपा को कांग्रेस भारत को बांटना चाहती है का नैरेटिव दे गए। कांग्रेस 99 सीटों पर रुकी, जबकि भाजपा 240 पर। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि ये पित्रोदा के निजी विचार हैं। अब 2025 में भी पित्रोदा रुके नहीं। फरवरी में चीन को दुश्मन न मानने का बयान और सितंबर में बिहार चुनावों से पहले पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ कहना। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के एक बयान ने फिर से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वे पाकिस्तान गए थे, तो उन्हें वहां घर जैसा महसूस हुआ और ऐसा नहीं लगा कि वे किसी विदेशी देश में हैं। इस बयान पर सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे कांग्रेस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अब जब बिहार के चुनाव नजदीक है तो ऐसे में उनके इस बयान का इस्तेमाल तो जरूर होगा।

बिहार में पीएम मोदी की मां को गाली, बनेगा चुनावी मुद्दाः– अपनी स्वर्गीय माताजी के प्रति कांग्रेस, आरजेडी के मंच से अत्यंत अभद्र शब्द और गाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे थे। उन्होंने भोजपुरी में कहा था कि बिहार में माई का स्थान देवता–पित्तर से भी ऊपर होता है। उन्होंने इसे केवल अपनी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां–बहन और बेटी का अपमान बताया। पीएम का यह संबोधन सुन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखें छलछला आईं थी। राज्य भर में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और चार सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद बुलाया. यानी संदेश साफ़ है कि पीएम ने इस गाली के जवाब में भावुकता का पुट देकर कुछ ही महीने दूर विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की पिच तैयार कर दी है.।

चौकीदार चोर बयान भी पड़ा भारीः–

भारतीय राजनीति में नेताओं के बयान हमेशा से जनता को एकजुट करने का हथियार रहे हैं, लेकिन कभी–कभी ये नारे उसी को चोट पहुंचाते हैं, जो इन्हें गढ़ता है। जैसे साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का च्चौकीदार चोर है। नारा ऐसा ही घातक साबित हुआ। यह कहानी उस नारे की है, जो राफेल डील को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 126 राफेल विमानों की डील में भ्रष्टाचार किया। राहुल गांधी ने इसे जनता तक ले जाने के लिए एक तीखा, लेकिन सरल नारा चुनारू चौकीदार चोर है। उनका यह नारा 2014 में पीएम मोदी के मैं देश का चौकीदार हूं के जवाब में था, जिसे उन्होंने अपनी ईमानदार छवि को मजबूत किया था।

राहुल की रणनीति थी कि यह नारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को लामबंद करने का काम करेगा. उन्होंने रैलियों, सोशल मीडिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बार–बार दोहराया। लेकिन यह नारा व्यक्तिगत हमले में तब्दील हो गया। भारत की जनता, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां मोदी की छवि ईमानदार और साधारण थी, इसे गले से नीचे नहीं उतार पाई।

स्मृति ईरानी ने कहा कि-
वोट चोरी शब्द लोकतंत्र का अपमान है

गुलफ़िशा खान

ट्रोलिंग के असर पर उन्होंने कहा कि उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था, इसलिए वो ट्रोल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग से उन पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। साथ ही कहा, मुझे कांग्रेस की याद नहीं आती, लेकिन कांग्रेस मुझे जरूर याद करती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में ट्रोलिंग को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। ईरानी ने ट्रोलिंग किए जाने के सवाल पर कहा कि जो ट्रोल कर रहे थे, उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था इसलिए उन्होंने यह किया। इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि मर्यादा की परिधि में हम लोग शांति से अपनी बात रख सकते हैं और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह वोट चोरी शब्द सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है।

ट्रोलिंग को लेकर कहा कि मर्यादा की परिधि में हम लोग शांति से अपनी बात रख सकते हैं और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं, लेकिन आप बार–बार मर्यादा भंग करोगे। बार–बार प्रधानमंत्री का तीखा शब्दों में नहीं बल्कि निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ बोलोगे तो एक कार्यकर्ता वर्ग है जो जवाब देगा।

उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोग संसद में और संसद के बाहर मुद्दों पर बेहद वोकल हैं। हमने तथ्यों के आधार पर पर्याप्त रूप से बात की है और जब तथ्यों या मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने ट्रोल किया। भद्दी–भद्दी बातें कही, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि मैं विक्टिव कार्ड प्ले करूं तो जिस मुद्दे पर मैं लड़ी हूं वो अप्रभावी हो जाता है। ट्रोलिंग के असर पर उन्होंने कहा कि उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था, इसलिए वो ट्रोल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग से उन पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। साथ ही कहा, मुझे कांग्रेस की याद नहीं आती, लेकिन कांग्रेस मुझे जरूर याद करती है। साथ ही कहा कि मेरे जैसे लोग राजनीति में आए हैं, उनकी इच्छा देश के लिए काम करने की है।

वोट चोरी पर भी बोलीं स्मृति ईरानी:- स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह वोट चोरी शब्द सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है क्योंकि यह विपक्ष द्वारा किया गया हमला है, जब वह मतदाताओं का विश्वास जीतने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारतीय मतदाताओं ने आप पर विश्वास नहीं किया है तो अब इसलिए विपक्ष ने अब उसी चुनाव आयोग पर हमला करने का फैसला किया है जो हमारे देश में लोकतंत्र सुनिश्चित करता है और उसी मीडिया को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने वाली किसी चूक की सूचना देती है। साथ ही उन्होंने इसे न्यायपालिका का भी अपमान बताया।

विपक्ष को युवाओं पर भरोसा नहीं:- युवाओं के राजनीति से जुड़ाव पर स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को लगता है कि युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते हैं तो उन्हें युवाओं पर भरोसा नहीं है और यह राजनीतिक जुड़ाव दर्शाता है कि उन्हें व्यवस्था में विश्वास है।

मेरे रचनात्मक कार्यों पर असर नहीं:- साथ ही इस दौरान समृति ईरानी ने कहा कि एक रचनात्मक व्यक्ति होने के नाते, मेरा राजनीतिक व्यक्तित्व मेरे रचनात्मक कार्यों पर असर नहीं डालता है।

'वोट चोरी' प्रकरण पर सुप्रिया सुले ने कहा- आंकड़ों पर बहस ज़रूरी

खलीक जाफ़री

देश में षायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां गाहे–बगाहे बिहार में हुई एसआईआर और कांग्रेस तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के सवालों पर बहस न होती हो। निर्वाचन आयोग की माने तो अब तो पूरे देष में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। माना जा रहा है कि जिसकी षुरूआत पष्चिम बंगाल से होगी। और जहां विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं। देखने वाली बात यह है कि चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी के सवाल इस विशय पर पाले खींच चुके हैं। केन्द्र की गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा और उसके सहयोगी जहां इस मामले में पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के साथ है तो वहीं दूसरी ओर लगभग पूरा विपक्ष निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। समर्थन और विरोध की इस गहमागहमी के बीच इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस दौरान कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल जो उठे हैं। यह कारण नहीं हैं कई पूर्व मुख्य चुनावों आयुक्तों ने इस बात को जोर देकर कहा है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह इसकी जांच करे। देखने वाली बात यह है कि वोट चोरी के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग मामले से मुंह छिपाने की मुद्रा है।

वहीं दूसरी ओर इधर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लगातार 'वोट चोरी' के आरोप के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें ठीक करने की जरूरत है। सुप्रिया सुले ने एक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि अगर आंकड़े हैं तो इस पर बहस होनी चाहिए। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस देश में कभी–कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस देश के सिस्टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। सुप्रिया सुले ने कार्यक्रम में कहा, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम आंकड़ों पर बहस न करें। अगर खामियां हैं तो व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, चुनौतियां हैं और आंकड़े शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। यह वो जनरेशन है जो कि सबूत मांगती है और यह डाटा पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप इस पर बहस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज को चुनौती दे रहे हैं।

केन्द्र की गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा और उसके सहयोगी जहां इस मामले में पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के साथ है तो वहीं दूसरी ओर लगभग पूरा विपक्ष निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। समर्थन और विरोध की इस गहमागहमी के बीच इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस दौरान कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल जो उठे हैं।

मेरी सीट से शुरू करें इंक्वायरीः- उन्होंने कहा, अगर आपको वोट चोरी की इंक्वायरी करनी है तो आप मेरी ही सीट से शुरू कीजिए. मैं क्यों दूसरे लोगों की तरफ उंगली उठाऊं। यदि आप एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं तो याद रखिए कि एक उंगली आपकी ओर भी उठती है।

सिस्टम और लोगों पर है विश्वासः- साथ ही कहा, इस देश में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हर देश में होता है। लेकिन इस देश के सिस्टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। एक सशक्त लोकतंत्र में चुनाव अच्छे से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर किसी ने कोई सवाल किया है तो उसका पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन सही जवाब देगा।

इलाहाबाद- तमिल संगम

अंजनी कुमार पांडेय

यू बचपन से संगम जाता रहा हूँ। जब दिल दिमाग मे धर्म की स्थापना नही हुई थी, तब संगम और उसके आस पास की तमाम जगहें मेरे लिये सिर्फ़ घूमने और मौज मस्ती की जगह हुआ करती थीं। अकबर का क़िला, बड़े हनुमान जी का मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर , सरस्वती घाट और शंकर विमान मंदिर। इन सभी मे शंकर विमान मंदिर मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। उसकी एक ही वजह थी कि वह सबसे अलग दिखता था। बचपन मे पहली बार मई की तपती गरमी के बीच मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था। उस वक़्त तक मैने अपनी ज़िंदगी मे इतना बड़ा मंदिर नही देखा था। मुझे याद है दोपहर से शाम तक खूब खेला था मै वहां पर ।

धर्म की स्थापना के बाद भगवान और

मंदिर का ज्ञान हुआ। फिर इतिहास पढ़ने के बाद मंदिर स्थापत्य कला की जानकारी हुई । फिर जाकर यह पता चला कि शंकर विमान मंदिर अलग इसलिये दिखता था क्योकि वह मंदिर द्रविड़ शैली मे बनाया गया है जो अमूमन दक्षिण भारत मे मिलती है । उत्तर भारत मे नागर शैली के मंदिर बनते हैं जिसमे शिखर होते हैं और अमूमन एक मंज़िल के ही होते हैं । द्रविड़ शैली के मंदिर हमेशा बहुमंजिला होते हैं और उनमें चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, गर्भगृह, पिरामिडनुमा शिखर, मंडप , विशाल प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर जरूर होते हैं। शंकर विमान मंदिर भी ऐसा ही है ।

गंगा,यमुना और अदृश्य सरस्वती की मिलन स्थली संगम से कुछ दूरी पर स्थित है द्रविड़ कलाकृति का अद्भुत एवं नायाब नमूना शंकर विमान मंडपम्। संगम जाने वाले हर किसी का ध्यान यह विशालकाय मंदिर अपनी ओर आकर्षित करता है। कम लोग ही जानते हैं कि इस भव्य मंदिर का निर्माण कांचिकामकोटि के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने अपनी गुरु की इच्छापूर्ति के लिए कराया था। जयेंद्र सरस्वती के गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती 1934 में प्रयाग यात्रा पर आये थे।

दारागंज स्थित एक आश्रम में रुके थे और वहां से प्रतिदिन पैदल संगम स्नान को जाते थे।संगम के पास उन्हें दो पीपल के वृक्ष के बीच एक खाली जगह नजर आयी , जो उन्हे बार बार आकर्षित करती थी। उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन एवं स्वयं के तपोबल से यह पता लगाया कि इस स्थान पर आदि शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट के बीच संवाद हुआ था। बाद में वहीं पर कुमारिल भट्ट ने तुषाग्नी में आत्मदाह किया था। इसलिये चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने इस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसे उनके शिष्य जयेंद्र सरस्वती ने पूर्ण की। इस मंदिर को बनने मे 17 साल का समय लगा था ।

इसकी नींव 1969 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी. गोपाल रेड्डी के हाथों रखी गयी। मंदिर 17 मार्च 1986 को जयेंद्र सरस्वती के हाथों भक्तों के लिए खोला गया। शंकरविमान मंडपम् मंदिर समर्पित है काँची कामकोटि पीठ की आराध्य कामाक्षी देवी को, भगवान विष्णु के तिरूपति बाला जी स्वरूप एवं भगवान शंकर को। इलाहाबाद और द्रविड़ प्रदेश का यह संगम अद्वितीय है ।

संगम जाने पर अभी भी दूर से ही दिख जाता है यह मंदिर और फिर इसकी चहारदीवारी मे खेले गये वो सारे खेल बरबस ही याद आ जाते हैं।

“हिंदू एकता के नायक”

एक मुख्यमंत्री, जिसने आस्था को शासन और राष्ट्रनिर्माण की धुरी बना दिया

मनीष कुमार पाण्डेय

भारत की राजनीति में लंबे समय तक जातीय समीकरणों का जाल ऐसा बिछा कि विकास, आस्था और राष्ट्रहित पीछे छूट गए। हर दल ने अपने–अपने 'वोट बैंक' बनाए और जातीय गोलबंदी को ही सफलता का सूत्र मान लिया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, तो उन्हें लगा कि यह चेहरा कुछ अलग है कि यह नेता "सत्ता" नहीं, "संस्कार" लेकर आया है। योगी आदित्यनाथ का शासन केवल प्रशासनिक अनुशासन का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि वाला राजनीतिक प्रयोग भी है। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा स्पष्ट हो तो सत्ता जनहित के लिए संकल्प बन सकती है।

उनका संदेश साफ़ है कि "विकास का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक राष्ट्र का आत्मा ज़रूर होती है।" योगी ने इस आत्मा को जगाया। उन्होंने प्रतिमा लगाई तो राम की, सड़क बनाई तो

काम की, और मिट्टी में मिलाया तो माफ़ियाओं को। उनके फैसलों में न व्यक्तिगत द्वेष है, न राजनीतिक प्रतिशोध कृ बस राष्ट्रहित की एकनिष्ठ साधना है।

जातीय समीकरणों से परे एक नया सामाजिक संतुलन

'योगी आदित्यनाथ ने जाति की दीवारें तोड़कर हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझा कि जब तक समाज धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि संस्कृति और कर्तव्य के नाम पर एकजुट नहीं होगा, तब तक भारत अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के गाँवों, कस्बों और नगरों में यह बदलाव दिखता है। जहाँ पहले राजनीतिक दल जातीय वोटों के हिसाब से रैलियाँ करते थे, वहाँ अब मंदिरों, तीर्थों और परंपराओं के पुनर्जीवन से समाज का आत्मबल बढ़ रहा है। यह केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं है—यह सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया कदम है। योगी आदित्यनाथ के शासन में "धर्म" का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य बन गया है। उन्होंने धर्म को शासन से अलग नहीं किया, बल्कि शासन को धर्म का साधन बना दिया। इसलिए, अयोध्या का दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं —आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। काशी का पुनरुद्धार केवल मंदिर का निर्माण नहीं कि सांस्कृतिक पुनर्जन्म का संकेत है। और मथुरा—वृंदावन की योजनाएँ बताती हैं कि विरासत और विकास एक—दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। उन्होंने दिखाया कि रामराज्य की अवधारणा केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि सुशासन का सबसे प्रासंगिक मॉडल है।

शासनिक दृढ़ता और नैतिक अनुशासन

योगी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कठोर लेकिन न्यायपूर्ण छवि है। वे उन गिने—चुने नेताओं में हैं जो सत्ता के सामने नहीं झुकते, बल्कि सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं। माफ़िया राज हो, अराजकता हो या प्रशासनिक भ्रष्टाचार उन्होंने हर स्तर पर यह संदेश दिया कि "राज्य में अब कोई अराजक तत्व नहीं चलेगा।" उनका शासन डर नहीं, भरोसा पैदा करता है। क्योंकि जनता देख रही है कि जो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी चाहे वह कोई भी क्यों न हो। और यही वह नीति है जिसने उन्हें विपक्ष के निशाने पर भी और जनता के दिलों में भी एकसाथ स्थापित किया है।

योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक विचार हैं

वह विचार जो कहता है कि भारत का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब वह अपने अतीत पर गर्व करेगा। उन्होंने इतिहास के उन हिस्सों को फिर से उजागर किया है, जिन्हें जानबूझकर दबाया गया। उनकी भाषा में आक्रोश नहीं, बल्कि चेतना है। उनका लक्ष्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति "पॉलिटिक्स ऑफ़ फेथ" नहीं, बल्कि "पॉलिटिक्स ऑफ़ कन्विक्शन" है। एक ऐसी राजनीति जो आस्था और राष्ट्रहित को एक सूत्र में बाँधती है। वह दलगत सीमाओं से परे एक नई वैचारिक रेखा खींच चुके हैं। जहाँ विकास को धर्म का विस्तार माना गया है, और राष्ट्रवाद को शासन का मूल

तत्व। उनका प्रयोग बताता है कि जब कोई नेता धर्म, कर्तव्य और देश इन तीनों को एक साथ जीता है, तो वह केवल लोकप्रिय नहीं होता बल्कि ऐतिहासिक बन जाता है।

योगी आदित्यनाथ उसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं

जहाँ हिंदुत्व और सुशासन मिलकर भारत के पुनर्जागरण की गाथा लिख रहे हैं। योगी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक वैचारिक क्रांति के सूत्रधार हैं। उन्होंने यह साबित किया कि हिंदू समाज को बाँटने वाली जातीय राजनीति अब अप्रासंगिक हो चुकी है। और वह युग अब शुरू हो चुका है, जहाँ "रामराज्य" केवल एक सपना नहीं, बल्कि नीति–निर्देशक सिद्धांत बन चुका है।

अपने नेतृत्व में आस्था को शासन और राष्ट्र निर्माण की धुरी बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने हिन्दू एकता के लिए पिछले दिनों एक बड़ा फैसला किया। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने समाज में जाति आधारित विद्वेष को ही नहीं बल्कि विभेद को भी समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सद्भाव के साथ सबके विकास को बल देने का सूझबूझभरा फैसला लिया है। इस फैसले के अन्तर्गत उन्होंने जाति–आधारित रैलियों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति संबंधी उल्लेखों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, लेकिन इसका वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक है। यह केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है। राजनीतिक दलों ने जाति आधारित वोटों को लुभाने एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिये समाज को बांटा है। यह गौर करने की बात है कि जाति आधारित संगठनों और रैलियों की बाढ़ आ गई है, जिससे एक–एक जाति के अनेक संगठन बने और इन जातिगत संगठनों ने सड़कों पर उतर कर न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, इंसान–इंसान के बीच दूरियां–विद्वेष बढ़ा दिया बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी क्षत–विक्षत कर दिया।

योगी आदित्यनाथ के शासन में "धर्म" का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य बन गया है। उन्होंने धर्म को शासन से अलग नहीं किया, बल्कि शासन को धर्म का साधन बना दिया। इसलिए, अयोध्या का दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं –आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। काशी का पुनरुद्धार केवल मंदिर का निर्माण नहीं कि सांस्कृतिक पुनर्जन्म का संकेत है।

त्वरित, कठोर और समयानुकूल निर्णय क्षमता ही है नरेन्द्र मोदी की पहचान

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मार्निंग कंसल्ट की वैश्विक मंच पर लोकप्रियता के ताजातरीन सर्वे में एक बार फिर 75 वर्षीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की लोकप्रियता या यों कहें कि एप्रूवल रेट 75 प्रतिशत रही है। यह विश्व के अन्य नेताओं की तुलना में कहीं अधिक है तो दूसरी और पिछले दिनों प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताने वाले केवल 40 प्रतिशत लोग ही रह गए और इनमें भी केवल मात्र 15 फीसदी ही ऐसे लोग है जो पूरी तरह से ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं। चुनाव के समय 81 प्रतिषत भरोसे लायक नेता पर 40 प्रतिशत अमेरिकीयों का भरोसा और इनमें से भी 25 प्रतिशत का थोड़ा भरोसा तो केवल 15 प्रतिशत अमेरिकी ही ट्रंप पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं। 59 प्रतिशत अमेरिकीयों को तो ट्रंप पर अब बिलकुल भी भरोसा नहीं रहा है। एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि मार्निंग कंसल्ट के इस सर्वे में दूसरे पायदान पर रहने वाले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति लीजे म्युंग को 59 प्रतिशत और अर्जेटिना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को 57 प्रतिशत का एप्रूवल मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एप्रूवल देश में ही नहीं विदेशों में भी एक दंबग नेता और साफ सुथरी छवि के कारण है। इसके साथ ही

कूटनीति, तकनीक, रक्षा, अर्थव्यवस्था और किसी के सामने नई झुकने की जीद ने और अधिक लोकप्रियता बढ़ा दी है। सबसे खासबात यह है कि विरोधी चाहे कितना भी शोर मचाये इसमें कोई दो राय नहीं और इससे भी बढ़कर कि आपरेशन सिन्दुर को लेकर देशवासियों और विदेशियों किसी को भी नरेन्द्र मोदी और सेना के कथन पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। देर सबेर और गाहे बेगाहे पाकिस्तान तक ऑपरेशन सिन्दुर की टीस को व्यक्त कर ही देता है। ऐसे में विरोधियों द्वारा ऑपरेशन सिन्दुर पर जिस तरह से नकारात्मकता व्यक्त की जाती हैं वह कहीं ना कहीं मोदी और मोदी सरकार की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने में ही सहायक है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नरेन्द्र मोदी अपनी जीवन की अमृतवेला मना रहे है। 75 साल के नरेन्द्र मोदी जिस अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं और खासतौर से जिस तरह से अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से पूरी तरह नकार कर लगता है अब तो ट्रंप को ही झुकने को मजबूर होने जैसे हालात कर दिए हैं। ट्रंप शायद भूल गए

कि यह आज का और मोदी का हिन्दुस्तान है। आज मोदी के भारत को दुनिया का कोई देश या दुनिया का कोई नेता हल्के में नहीं ले सकता। इसका कारण भी है भारत आज आंख में आंख डाल कर बात करने की हैसियत रखता है। ट्रंप की बौखलाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल आज के दौर में वैश्विक नेता के रुप में बोल्ड होने, एग्रेसिव होने, कठोर व त्वरित निर्णय लेने वाले नेता लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। अच्छे बुरे परिणाम की चिंता कर निर्णय की उहापोह में फंसे नेता आज के लोगों की पसंद हो ही नहीं सकते। इसका बड़ा कारण दुनिया में वैश्विक संकटों का दौर चलना है। पर यह भी समझ लेना होगा कि दुनिया के लोग ट्रंप जैसे अंहकारी, तुगलकी निर्णय करने वाले, गली मौहल्ले के दादाओं जैसे व्यवहार करने वाले और अपने नासमझी भरे निर्णयों और फिर उन निर्णयों पर मुहं की खाने वाले नेताओ को भी पसंद नहीं करते। संकटों के दौर में लोगों का यह मानना रहता है कि हमें आलोचना प्रत्यालोचना या आगा पीछा सोच कर निर्णय लेने वाला नहीं अपितु त्वरित और कठोर निर्णय लेने वाला नेता चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी इस पर खरे उतरे हैं। जहां तक देश और देश में मोदी विरोधियों की बात है तो यह भी अब तक साफ हो गया है कि मोदी के विरोध में जो जो नारे गढ़े गए या अभियानों में जो मोदी विरोध की आवाज बने वह सब विरोधियों पर ही भारी पड़े है। इसकी शुरुआत 2007 में गोदरा कांड के बाद चुनाव के बाद का नारा मौत का सौदागर हो या आज चौकीदार चोर है सभी नारे उल्टे पड़े हैं और देशवासियों ने इन्हें सिरे से नकारा है। चौकीदार चोर है का उत्तर देते हुए स्वयं मोदी ने इसका उपयोग मैं भी चौकीदार का जबावी नारा देकर उत्तर दिया। नारों की यह एक लंबी फेहरिस्त है जिससे देशवासी अवगत है। अब आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर या संविधान बचाओं का नारा देकर मोदी विरोध में हवा बनाने व बिहार आदि के चुनाव जीतने का सपना पाल रहे हैं पर कहीं पहले की तरह सेल्फ गोल ही साबित ना हो जाये इससे नकारा नहीं जा सकता। राममंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाने, कश्मीर युवाओं को मुख्यधारा में लाने, ऑपरेशन सिन्दुर, एयर स्ट्राइक, जनधन खाते, डिजिटल भुगतान, जन औषधी केन्द्र, आयुष्मान योजना, गिग इकोनोमी, रक्षा आयुधों का देश में ही उत्पादन व निर्यात, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप, यूनिकोर्न, विदेशी निवेश, सडक परिवहन विकास, आदि आदि सभी क्षेत्रों में विकास का जो दौर दिखाई दे रहा है यह ठोस और त्वरित योजनावद्ध निर्णयों का ही परिणाम है। यह तो केवल बानगी मात्र है। आज आतंकवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई, नक्सलवादी गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, सांप्रदायिकता पर रोक लगी है, पत्थरबाजी नहीं दिखती, सपाट यातायात दिखाई दे रहा है यह और इसके अलावा भी बहुत कुछ सामने हैं।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि विश्वसनीयता एक दिन में या एक काम से नहीं बनती। इसके साथ ही केवल व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने से भी कोई खास हासिल नहीं हो सकता। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की आदत डाले तो शायद आमजनता में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी बात रख कर लोगों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय अस्मिता पर और सेना के पराक्रम को प्रश्नों में उभारा जाता है तो लाख कमियों के बावजूद सच्चा राष्ट्रप्रेमी नागरिक इसे स्वीकार नहीं पाता। यही कारण है कि मोदी जी को जितना निशाना बनाया जाता है मोदी उस निशाने से और अधिक निखार के साथ उभरते आ रहे हैं। आज जब ट्रंप भारत की अर्थ व्यवस्था को नकारते हैं तो यह देशवासियों के गले उतरने वाली बात नहीं होती। इसी तरह से जब ऑपरेशन सिन्दुर पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो आमजन इसे देश के खिलाफ आवाज और सेना के असम्मान के रुप में देखता है। जब संविधान की प्रति उठाकर संविधान बचाओ की बात करते हैं तो उनकी सरकार के समय ही संसद से पास अधिसूचना को सार्वजनिक रुप से फाड़ने को याद करते हैं। जीएसटी को लेकर प्रश्न उठाते हैं तो आज इससे मिल रही राहत को जनता कैसे नकार सकती है। इसलिए सकारात्मक विरोध के साथ आगे आकर ही मोदी और मोदी की नीतियों का पार पा सकते हैं।

संसद और विधानसभाओं में गतिरोध का दौर चलता है, खुली चर्चाएं हो नहीं पाती, सत्र सालों साल छोटे होते जा रहे हैं। आधी आधी रात तक होने वाली चर्चाएं अब बीते दिनों की बात हो गई है तो ऐसे में केवल आरोप प्रत्यारोप के भरोसे मोदी पर जीत की बात करना बेमानी होगा। दूसरी बात यह कि हम बड़ी लकीर खींच कर ही दूसरी लकीर को छोटी बता सकते हैं हो इसका उल्टा रहा है और प्रयास लकीर से ही छेड़ छोड़ कर छोटी दिखाने के प्रयास किये जाते हैं तो यह गले नहीं उतरती। यह सब समझने वाली बात हो गई है। मोदी जी की अमृत वेला में शतायु होने की कामना के साथ आज देश उनकी और देख रहा है। ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व और निवृति की बात करना पूरी तरह से बेमानी होगी। देश को अभी मोदी जी और उनके जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिससे आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन कर उभर सके।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हुई है- सांसद भाजपा कंगना रनौत का छलका दर्द

दिल्ली ब्यूरो

मंडी से हाल ही में सांसद बनीं और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों मनाली के अपने रेस्तरां की कम बिक्री से परेशान हैं. हाल ही में मनाली दौरे के दौरान उन्होंने अपना दर्द वहां मौजूद लोगों और मीडिया से साझा किया। कंगना के मुताबिक, उनके रेस्तरां की एक दिन की बिक्री केवल रू. 50 रही, जबकि स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च रू. 15 लाख तक पहुंच गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत आपदा के बाद मनाली पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने यहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। मनाली पलचान गांव में हुई तबाही को उन्होंने देखा।

कंगना रनौत ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की रहने वाली हूं। लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं, लेकिन मेरा दर्द भी समझो। मैं एक सिंगल वुमन हूं। मेरे रेस्तरां की सेल सिर्फ रू. 50 है और खर्च रू.15 लाख। केंद्र सरकार ने आपदा के लिए रू. 10,000 दिए हैं। कंगना इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रही थी।

> *“केंद्र की राशि की गणना अगर प्रदेश सरकार करेगी ही नहीं और उस फंड की कहीं गिनती भी नहीं होगी तो केंद्र प्रदेश की सहायता क्यों करेगा। मनाली में आपदा प्रभावित लोगों से कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रही हैं। लेकिन हिमाचल सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं।*

इस घटनाक्रम से पता चलता है कि एक तरफ़ जहां कंगना राजनीति में नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, वहीं उन्हें अपने व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है, जहां लोग उनके दर्द को समझने और उनकी व्यावसायिक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र का आभार करना सीखे। केंद्र की राशि की गणना अगर प्रदेश सरकार करेगी ही नहीं और उस फंड की कहीं गिनती भी नहीं होगी तो केंद्र प्रदेश की सहायता क्यों करेगा। मनाली में आपदा प्रभावित लोगों से कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रही हैं। लेकिन हिमाचल सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। अब तक 10 हजार करोड़ की मदद केंद्र सरकार ने की। आने वाले समय में और भी मदद करेगी।

अडाणी को क्लीन चिट मिलने के बाद क्या अब हिंडनबर्ग और राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे

नीरज कुमार दुबे

जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट–सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों में शुमार अडाणी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों का स्वरूप इतना सनसनीखेज था कि देखते ही देखते शेयर बाज़ार में भूचाल आ गया। करोड़ों निवेशकों की मेहनत की कमाई रातों–रात डूब गई और भारत की वैश्विक आर्थिक साख पर प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश हुई। यह केवल एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं था, बल्कि भारत की औद्योगिक प्रगति को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश थी।

हम आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग ने अपने तथाकथित रिसर्च रिपोर्ट में अडाणी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फर्जी अकाउंटिंग के आरोप लगाए। रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई जब अडाणी एंटरप्राइजेज अपना 20,000 करोड़ रुपये का मेगा पब्लिक ऑफर लाने जा रही थी। इसका सीधा असर यह हुआ कि निवेशकों का विश्वास हिल गया और शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हुई। चिंता की बात यह थी कि भारत के कुछ विपक्षी दलों ने भी इस रिपोर्ट को सच मानकर इतना दुष्प्रचार किया मानो पूरा अडाणी समूह भ्रष्टाचार और घोटालों का अड्डा हो। संसद से लेकर सड़क तक इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई। इस राजनीतिकरण ने विदेशी निवेशकों में भी भ्रम फैलाया और भारत के कॉर्पोरेट जगत की विश्वसनीयता पर आघात पहुँचा।

लेकिन लगभग दो साल की लंबी और गहन जाँच के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने साफ कह दिया है कि अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और आधारहीन थे। जाँच में पाया गया कि जिन वित्तीय लेन–देन को हिंडनबर्ग ने "फर्जी" बताया, वे सब कानूनी रूप से वैध ऋण और पुनर्भुगतान थे। न तो धन का गबन हुआ, न ही किसी अवैध पार्टी को फायदा पहुँचाया गया। यहाँ तक कि जाँच के दौरान लिए गए सभी ऋण ब्याज समेत वापस किए गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने आदेश में

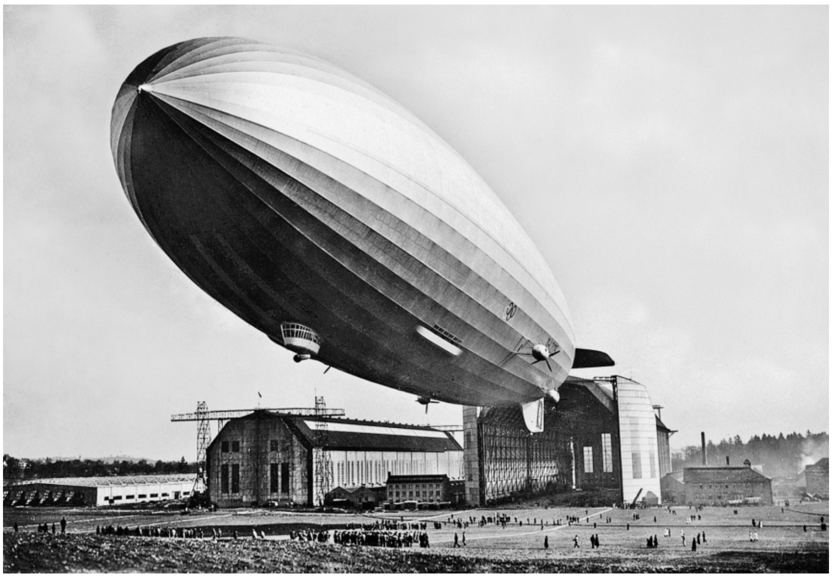

यह भी कहा कि इन लेन–देन को "रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन" या "फर्जीवाड़ा" नहीं कहा जा सकता। यानी, आरोपों का कोई कानूनी या आर्थिक आधार ही नहीं था।

देखा जाये तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते जो हुआ, वह किसी भी देश के उद्योग जगत के लिए चेतावनी है। अडाणी समूह के शेयरों में अचानक भारी गिरावट आई। छोटे–बड़े करोड़ों निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। यह नुकसान केवल अडाणी का नहीं था, बल्कि भारत के वित्तीय बाजार और निवेश माहौल का भी था। गौतम अडाणी ने स्वयं कहा कि इस विवाद से उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि आम निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह कथन उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाता है और यह भी बताता है कि एक सुनियोजित झूठ कितनी बड़ी आर्थिक तबाही ला सकता है। देखा जाये तो हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट मात्र एक रिसर्च डॉक्युमेंट नहीं थी। यह स्पष्ट था कि इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ छिपे हुए थे। एक तरफ अमेरिकी और पश्चिमी ताकतें भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और उसके वैश्विक प्रभाव से चिंतित थीं, दूसरी तरफ कुछ घरेलू राजनीतिक दलों ने इसे अपने लाभ के लिए हथियार बना लिया। इस साजिश का परिणाम यह हुआ कि भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश हुई। विदेशी मीडिया ने भी इस विवाद को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया। परंतु समय ने साबित कर दिया कि यह सब केवल भारत की औद्योगिक क्षमता को चोट पहुँचाने का प्रयास था।

अब जबकि सेबी की रिपोर्ट ने सभी आरोपों को झूठा सिद्ध कर दिया है, तो सबसे पहला कर्तव्य हिंडनबर्ग और उनके समर्थकों का बनता है कि वे भारत और निवेशकों से माफी मांगें। इसके साथ ही, भारत के विपक्षी दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या केवल राजनीतिक विरोध के लिए वे ऐसी

अंतरराष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा बन सकते हैं? लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जरूरी है, लेकिन जब बात राष्ट्रहित और निवेशकों के विश्वास की हो, तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।

हिंडनबर्ग रिसर्च तो अपनी कंपनी बंद कर चुका है, लेकिन उसकी अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर देश की संसद का पूरा सत्र ठप करने वाले विपक्षी दल आज भी सक्रिय हैं। उस समय जिस तरह से उन्होंने निराधार आरोपों को हवा दी, विदेशी एजेंडे को ताक़त दी और करोड़ों निवेशकों के भरोसे को चोट पहुँचाई, वह केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ था। आज जबकि सच सामने आ चुका है और नियामक संस्था ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, विपक्षी दलों को कम से कम देश और जनता से माफी माँगनी चाहिए।

बहरहाल, हिंडनबर्ग प्रकरण ने हमें यह सिखाया है कि किसी विदेशी रिपोर्ट या आरोप को आँख मूँदकर सच नहीं मान लेना चाहिए। इस मामले ने करोड़ों निवेशकों को झकझोरा, अडाणी समूह की छवि को धक्का पहुँचाया और भारत की साख को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी। परंतु अंततः सच्चाई सामने आई और स्पष्ट हुआ कि यह सब एक रचा–बसा षड्यंत्र था। अब समय आ गया है कि न केवल हिंडनबर्ग, बल्कि इस साजिश में शामिल राजनीतिक ताकतें भी देश और निवेशकों से सार्वजनिक रूप से माफी माँगें। क्योंकि भारत की औद्योगिक प्रगति किसी एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। और उस पर चोट करना सीधे–सीधे राष्ट्रहित पर चोट करना है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

कमलेश पांडे

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन उसके कुछेक प्रावधानों में विधिसम्मत और तर्कसंगत संशोधन किया है या फिर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसलिए वक्फ संशोधन अधिनियम में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने समझना बहुत जरूरी है। लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट के इस ताजातरीन फैसले से वे आशंकाएं दूर हो जाएंगी, जो इस नए कानून को लेकर इससे पहले जताई जा रही थीं। चूंकि कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुरूप है, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे मान लिया है। यह एक शुभ लक्षण है।

बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए संशोधन महत्वपूर्ण और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें संविधान की भावनाओं का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसके परिवर्तित मायने राष्ट्रीय एकता के लिहाज से अहम हैं। लिहाजा इस फैसले का मुख्य असर निम्नलिखित है–

पहला, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, बताया गया है। हालांकि यह रोक तभी तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकारें इसके लिए अलग से नियम नहीं बना देतीं। चूंकि यह शर्त मनमानी हो सकती थी, इसलिए अदालत ने इसे स्थगित कर दिया है। समझा जाता है कि वक्फ करने के लिए न्यूनतम 5 बरसों तक इस्लाम का अनुयायी होने के प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी, जब तक राज्य सरकारें इसके सत्यापन के लिए नियम नहीं बना लेती। चूंकि देश में धर्म व्यक्तिगत मामला है और यह जरूरी नहीं कि कोई नागरिक अपनी धार्मिक पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन करे। इसलिए यह तय करना कि कोई किसी धर्म को कब से मान रहा है, बेहद जटिल है। राज्य सरकारों से उम्मीद है कि इस बारे में नियम बनाते समय वे सभी पहलुओं का ध्यान रखेंगी और ज्यादा संवेदनशीलता बरतेंगी।

दूसरा, कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है कि जिला कलेक्टर को यह फैसला देने का अधिकार नहीं है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट अंतिम निर्णय न कर ले। इससे कलेक्टर की शक्ति

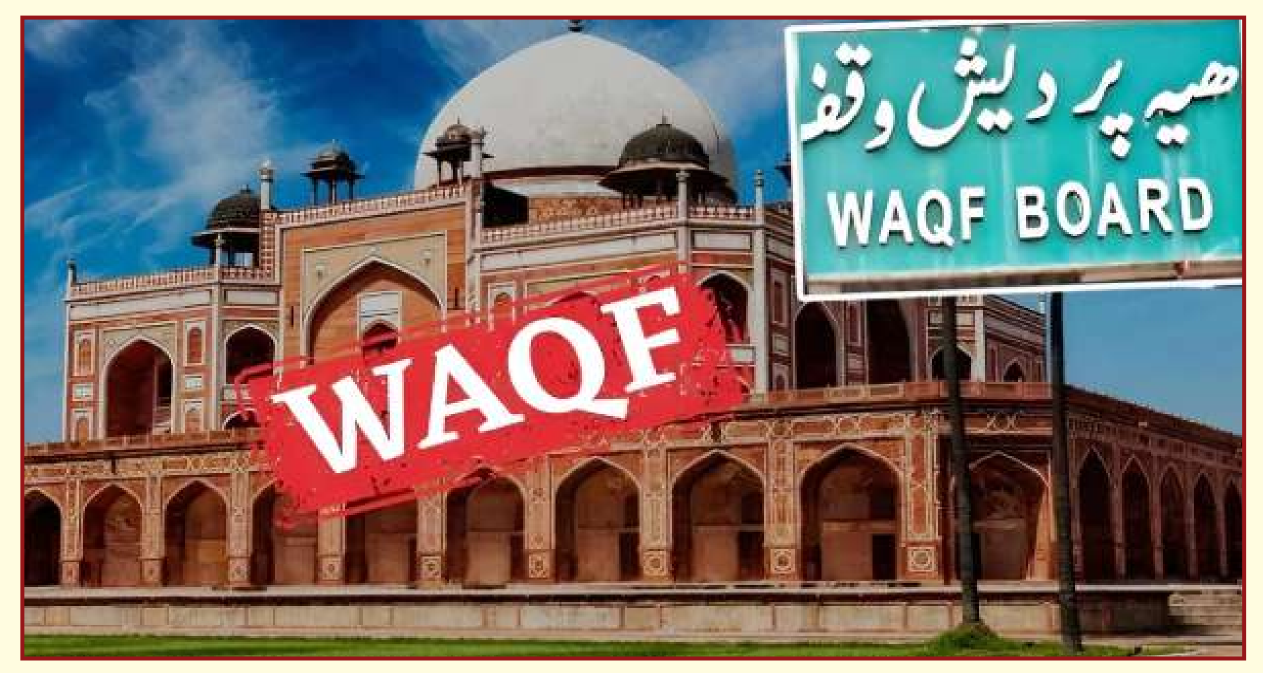

सीमित हुई है और मनमानी पर रोक लगी है। यह एक अहम संशोधन है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने वक्फ संपत्ति जांच के प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामित अधिकारी की आंशिक रूप से रिपोर्ट के आधार पर ही किसी प्रॉपर्टी को गैर–वक्फ नहीं माना जा सकता। समझा जाता है कि अदालत ने संपत्ति अधिकार तय करने की ताकत जिलाधिकारी को देने को संविधान में की गई व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ माना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि लोकतंत्र के तीनों अहम अंगों– विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। एक पक्ष की ओर पलड़े का थोड़ा भी झुकाव व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ देगा।

तीसरा, वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या और गैर–मुस्लिम सदस्यों की सीमा में संशोधन भी कुछ हद तक सुरक्षित की गई है, लेकिन कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर स्थगन लगाया है। लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी सरकार अन्य धर्मों के लिए भी इसी तरह के कानून लाएगी व उसका अनुपालन का निर्णय करेगी।

चतुर्थ, कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को शक्ति के श्मनमानेश प्रयोग को रोकने के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और बुजुर्गों का धर्म पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के कई बिंदुओं पर विपक्ष को गहरी आपत्ति थी। इसे लेकर दोनों सदनों में और सड़क पर भी काफी हंगामा हुआ। इस मामले की गंभीरता और उसके असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिम्मेदारी भरा है।

यूँ तो इस बाबत दायर याचिका में पूरे कानून को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे नहीं माना। इस तरह के कदम बेहद दुर्लभ मामलों में उठाए जाते है और इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। देखा जाए तो इस मायने में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया, और यह भी ध्यान रखा कि विधायिका के साथ सीमाओं का अतिक्रमण न हो। इसलिए उसने समझदारी पूर्वक बीच का रास्ता निकाला है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में बेहद संतुलित नज़रिया अपनाया है।

सच कहा जाए तो कोर्ट का यह फैसला वक्फ कानून में संतुलित नज़रिया को अधिक न्यायसंगत और संवैधानिक बनाने की दिशा में संकेत देता है। साथ ही इसके मार्फ़त सरकारी शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बनाने का प्रयास भी किया गया है। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित कुछ नियम और प्रावधान तभी तक लागू नहीं होंगे, जब तक इस बारे में अधिक स्पष्ट नियम और निर्देश नहीं बन जाते। इस तरह से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। ऐसा करके उसने एक ओर जहां संतुलित नजरिया अपनाते हुए शक्ति का संतुलन बिठाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून पर फैसला देते हुए उसने अतिरिक्त संवेदनशीलता की जरूरत भी समझी है। यही वजह है कि अपेक्षाकृत विवादास्पद मामलों में उसका एक और जिम्मेदारी भरा निर्णय सामने आया है, जिससे देश–प्रदेश ने राहत की सांस ली है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

टेंशन बढ़ाती चौपहियाओं को खड़ी करने की समस्या

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

पिछले दिनों समाचार पत्रों में दो समाचारों की सुर्खियां प्रमुखता से देखी गई। पहला समाचार यह कि एक मोटे अनुमान के अनुसार नोएडा में साल भर में एक लाख से अधिक नए वाहन खरीदे जाते हैं तो दूसरा समाचार दिल्ली से जुड़ा है और इसमें यह कि दिल्ली में कहीं भी जाओं तो वाहन को पार्किंग के लिए खड़ा करने में औसतन 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। दोनों समाचार ही देष में आर्थिक उन्नती को दर्शाने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव को इंगित करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि हमारे शहर आज और आने वालों सालों के लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक और वाहनों की मांग और खरीद बढ़ती जा रही है और इसमें भी बड़ा बदलाव यह देखा जा रहा है कि अब लक्जीरियस वाहनों की खरीद को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है तो दूसरी और ऑफिस या किसी काम से घर से बाहर निकलने पर वाहन को पार्क करने की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि वाहनों की पार्किंग को लेकर तू तू मैं मैं, झगड़ा और मारपीट तो आम होती जा रही हैं वहीं वाहन खड़ा करने को लेकर जानलेवा हमला और जान ले लेने तक के समाचार अखबारों की यदा कदा सुर्खियां बनते जा रहे हैं। रोडरेज की घटनाएं आम होती जा रही है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि यह समस्या कोई नोएडा या दिल्ली की ही नहीं हैं अपितु कमोबेस यह समस्या देश के किसी भी शहर में गंभीर रुप लेती देखी जा सकती हैं। दरअसल हमारे नगर नियोजकों व शहरी नियामक संस्थाओं ने पार्किंग की समस्या को गंभीरता से लिया ही नहीं है। गांवों को निगलकर शहरों का विस्तार होता जा रहा है तो गगनचुंबी इमारते बनती जा रही है। आबादी का घनत्व और दबाव बढ़ता जा रहा हैं। जिस अनुपात में यह बदलाव आ रहा है उस अनुपात में भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों की और ध्या नही नहीं दिया जा रहा

है। आबादी के पास के एक समय के बड़े बड़े बंगले अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग और मॉल्स में तब्दील होते जा रहे हैं। जहां पहले एक बंगले से एक समय में एक या दो वाहनों का ही यातायात दबाव पड़ता था वहीं अब उसी स्थान पर बनें मल्टी स्टोरी में बहुत से फ्लेट्स होने के कारण बहुत से परिवार रहने के कारण औसतन डेढ़ गाड़ी का दबाव भी माना जाएं तो साफ हो जाता है कि रोड पर वाहनों का दबाव तो पड़ेगा ही। जहां तक मॉल्स का सवाल है अधिकतर माल्स में पार्किंग की सुविधा तो होती है पर अधिकांश पार्किंग तो माल्स में बिजनस प्रतिष्ठानों के मालिकों, कार्मिकों आदि से ही भर जाते हैं तो वहां आने वालों के लिए पार्किंग की समस्या बन ही जाती है। पार्किंग की समस्या को लेकर भी दो तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। एक तो यह कि अब घरों कालोनियों में भी वाहन पार्किंग की समस्यां गंभीर होती जा रही है। इसका बड़ा कारण एक ही परिवार में एक से अधिक वाहनों और वह भी लक्जीरियस वाहन एमयूवी/एसयूवी का होना आम होता जा रहा है तो दूसरी और सार्वजनिक परिवहन साधनों की योजनाबद्ध उपलब्धता नहीं होना है। कहने को तो अब ओला–उबेर की बात की जाने लगी है या दिल्ली–मुंबई जैसे बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन की बात की जा सकती है पर समस्या का समाधान यह इसलिए नहीं है कि नई कालोनियों के विकास के अनुसार इनकी सहज उपलब्धता का सवाल भी होता है। भले ही यह बात थोड़ी अजीब अवश्य लगे पर अब शहरों में घरेलू या यों कहें कि निजी चौपहिया वाहनों की पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। यह सही है कि यह समस्या केवल और केवल हमारे महानगरों तक सीमित ना होकर दुनिया के अधिकांश देशों के सामने तेजी से विस्तारित होती जा रही है।

दुनिया के देश चौपहिया वाहनों की पार्किंग समस्या से दो चार हो रहे हैं और इस समस्या के समाधान के लिए अनेक विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। यहां तक की पार्किंग शुल्क से अच्छी खासा आय होने लगी है। अकेले भारत की ही बात करें तो देश में पांच करोड़ से अधिक कारें चलन में हैं और हर साल में इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार दिल्ली में उपलब्ध कारों की पार्किंग के लिए ही चार हजार से अधिक फुटवाल के मैदानों जितनी जगह की आवश्यकता है। अगर दिल्ली की ही पार्किंग से आय की बात करें तो यह कोई 9800 करोड़ से अधिक की हो जाती है। देश के किसी भी कोने में किसी भी शहर की गलियों में निकल जाएं तो देखेंगे कि गलियों में घरों के बाहर सड़क की आधी जगह तो कारों के पार्किंग से ही सटी होती हैं। यानी कि एक ही घर में एक से अधिक कार/वाहन होना अब आम होता जा रहा है। किसी भी शहर में आफिस या बाजार खुलने बंद होने के समय तो जाम लग जाना आम होता जा रहा है। यह सब तो तब है जब आबादी की तुलना में कारों की संख्या कम है। आने वाले सालों में कारों की संख्या में इजाफा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

दरअसल इस सबके अनेक कारणों में से उपनगर विकसित करने पर ध्यान नहीं देना, व्यस्ततम स्थानों पर ही बहुमंजिला इमारतें बनाने की छूट देना, शहरी सार्वजनिक यातायात तंत्र का विकसित नहीं होना, वाहनों की खरीद सहज होना और वाहनों की पार्किंग के लिए दूरगामी योजना का अभाव होना माना जा सकता है। दरअसल चौपहिया वाहनों की जिस तरह से सुगम ऋण सुविधा व पैसों के तेजी से बढ़ते प्रवाह के कारण सहज पहुंच हुई है उसका एक सकारात्मक परिणाम यह सामने आया हैं कि जिस तरह से अमीर गरीब सभी के लिए मोबाइल आम होता जा रहा हैं ठीक उसी तरह से चौपहिया वाहन आम होता जा रहा हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की माने तो 2050 तक दुनिया के देशों में केवल और केवल कारों की पार्किंग के लिए ही 80 हजार वर्ग किलोमीटर स्थान की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह कि छोटा मोटा देश आसानी से इस जगह में समा सके। शहरी विकास संस्थाओं और योजना नियंताओं को निजी कारों की पार्किंग को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार करनी ही होगी। मजे की बात यह है कि अब कार बाजार इलेक्ट्रिक कारों में शिफ्ट होता जा रहा है, ऐसे में चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी समय रहते जगह तलाशनी होगी। पेड पार्किंग स्थानों पर ऑटोमेटिक बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था हो तो और भी अधिक सुविधाजनक हो सकती है। बहु मंजिला इमारतों और माल्स में भी पार्किंग की अधिक सुविधा होना समय की मांग हो गई है। दरअसल इस सबके लिए समय रहते दूरगामी नीति बनानी होगी ताकि समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ नहीं जाएं। वास्तुकारों और नियोजकों के लिए यह अपने आप में चुनौती पूर्ण काम हो गया है। किराए की पार्किंग व्यवस्था सस्ती व सहज उपलब्धता वाली भी होनी चाहिए। शहरी निकाय संस्थाओं को इस और गंभीरता से प्रयास करने होंगे वहीं कोलोनाइजरों को भी इस दिशा में पहले से ही रोडमेप बनाकर चलना होगा नहीं तो आने वाले समय में यह एक और नई समस्या दस्तक देने वाली है। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है एक और तो ऑटोमोबाईल उद्योग को बढ़ावा देना है तो दूसरी और पार्किंग की समस्या का कोई ना कोई योजनाबद्ध सहज हल खोजना होगा।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 ट्राफी विवाद को लेकर मोहसिन नकवी पर साधा निशाना

कुसुम

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि, मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेकर भागने के बाद से लगातार विवादों में है। उन्होंने ये ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम को नहीं लौटाई बल्कि यूएई बोर्ड में ट्रॉफी को हैंडओवर करके लाहौर चले गए।

28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। जिसे भारत ने पांच विकेट से जीत लिया लेकिन बाद में ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद तब हुआ जब एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नकवी से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया।

प्रेजेंटेशन लगभग एक घंटे तक टलता रहा क्योंकि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और नकवी स्टेज पर इतंजार करते रहे। हालांकि, नकवी अपने रुख से पीछे नहीं हटे और आखिर में समारोह बिना ट्रॉफी के ही खत्म हुआ। वहीं इस कड़ी में हरभजन सिंह का मानना है कि, नकवी की हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे इतने बड़े नहीं हैं कि ये तय करें कि ट्रॉफी भारत को दी जाए या नहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि, एशिया कप के दौरान बहुत कुछ हुआ। हैंडशेक विवाद से पहले तो बड़ा एशिया ये था कि क्या ये मैच होने भी चाहिए थे या नहीं। भारत ने टूर्नामेंट जीता है और वही उनकी सबसे

बड़ी ट्रॉफी है। मुझे नहीं लगता कि नकवी या कोई और इतना बड़ा है कि ये तय करें कि ट्रॉफी दी जाए या नहीं। आज नहीं तो कल ट्रॉफी भारत के पास आएगी ही जब जीत हमारी है तो उसे रोककर रखने का क्या मतलब है।

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद की कराची में शादी हुई जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। वह पिछले कई दिनों से एशिया कप 2025 ट्रॉफी के कारण चर्चा में है। अबरार की शादी में भी वह इस सवाल से बच नहीं पाए जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था। एक और सवाल नकवी से पूछा गया कि अब एशियाकप का भविष्य क्या है? इस पर एसीसी अध्यक्ष से बेशर्मी वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

दरअसल, एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को खेला गया था। जिसे भारत ने जीता और ट्रॉफी भी अपने नामकी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गए। फिलहाल, वह एसीसी के प्रमुख भी हैं।

नकवी जब अबरार की शादी में पहुंचे तो इसमें पाकिस्तान के कई खिलाड़ी भी मौजूद थे। शादी से निकलते हुए पत्रकार ने उनसे पूछा कि सूर्यकुमार यादव ने तो मना किया है कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया था। इस पर नकवी बेशर्मी से हंसते हुए दिखे साथ ही पत्रकार ने उनसे पूछा कि एशिया कप का भविष्य क्या है इस पर भी पीसीबी चीफ हंसते रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। हालांकि, बीसीसीआई इस मामले में लीगल एडवाइस ले रहा है। एसीसी की बैठक में भी बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी से इस बारे में सवाल पूछा। नकवी ने कहा था कि सूर्यकुमार यादव उनके ऑफिस में आकर ट्रॉफी ले सकते हैं। इस पर बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया था कि जब उनसे स्टेडियम में ट्रॉफी नहीं ली गई तो ऑफिस में आकर ट्रॉफी लेने का कोई सवाल नहीं बनता।

कैसे रश्मिका, एनटीआर, प्रभास बने ग्लोबल स्टार?

अंजुम शाहकार

भारतीय सिनेमा हाल के वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली कुछ सबसे बड़ी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों का गवाह रहा है। इन फिल्मों का नेतृत्व भारत के सबसे बड़े सितारों ने किया है, जिन्होंने अखिल भारतीय सनसनी के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। वे न केवल एक निश्चित क्षेत्र या इलाके में दिल जीत रहे हैं, बल्कि देशभर के सिनेमाघरों, फिल्मों और दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वे अब अखिल भारतीय सनसनी के रूप में पहचाने जाते हैं, यह सब उनके आकर्षक अभिनय, अविश्वसनीय स्क्रीन उपस्थिति, कड़ी मेहनत और उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की बदौलत है। उन्होंने न केवल दक्षिण में बल्कि पूरे देश और उसके बाहर भी बड़े पैमाने पर फैंस बनाए हैं। रश्मिका मंदाना से लेकर प्रभास और अन्य तक, यहां भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय सनसनी हैं जो सिनेमाघरों और सभी के दिलों पर राज कर रही हैं।

रश्मिका मंदाना, जिन्होंने कुछ साल पहले ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था। बहुत कम समय में तमिल और तेलुगु फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा डियर कॉमरेड, एनिमल, पुष्पा फ्रैंचाइज़ी, छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं। उनके पास एनिमल पार्क, पुष्पा 3, थामा जैसी कई फिल्में हैं जो उन्हें आज की सबसे बड़ी अखिल भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बनाती हैं।

प्रभास:-प्रभास निर्विवाद रूप से अखिल भारतीय सुपरस्टार में से एक हैं। उन्होंने बाहुबली फ्रैंचाइज़ी से अपने अखिल भारतीय सफ़र की शुरुआत की और फिर सलार और कल्कि 2898 ईस्वी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दीं, जो बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक बन गईं। इसके अलावा, उनकी आने वाली फ़िल्मों की एक और रोमांचक सूची है, जिसमें कल्कि 2898 ईस्वी का सीक्वल, द राजासाहब, स्पिरिट, सलाररू पार्ट 2 शौर्यंग पर्वम, और भी बहुत कुछ शामिल है।

अल्लू:- तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत से शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन अब सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी पुष्पा के साथ सबसे बड़े अखिल भारतीय सितारों में से एक हैं। वह पुष्पा

3–द रैम्पेज और दीपिका पादुकोण के साथ अपने आगामी बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपनी बादशाहत जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

एनटीआर:- एनटीआर अखिल भारतीय स्तर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सितारों में से एक हैं, जिन्होंने आरआरआर, देवरा और वॉर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं। इसके बाद, वह केजीएफ फिल्म निर्माता प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एनटीआरएक्सनील में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जो 25 जून, 2026 को रिलीज़ होने वाली है और अगले साल की सबसे बड़ी सिनेमाई फिल्मों में से एक होने का अनुमान है। खबर है कि वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक पौराणिक नाटक पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें वह पूज्य देवता भगवान कार्तिकेय की भूमिका निभाएंगे।

ऋषभ शेट्टी:- ऋषभ शेट्टी ने अखिल भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया और अपनी अभूतपूर्व फिल्म कंटारा से देशभर में सनसनी बन गए. उनके दमदार अभिनय ने देश भर के दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी सफलता के आधार पर, अब वह कंटारा चैप्टर 2 सहित कई बहुप्रतीक्षित अखिल भारतीय परियोजनाओं की तैयारी कर रहे हैं। वह पौराणिक महाकाव्य जय हनुमान और भव्य ऐतिहासिक नाटक द प्राइड ऑफ भारत– छत्रपति शिवाजी महाराज में भी नज़र आएंगे।

यश:-यश ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ–चैप्टर 2 की अभूतपूर्व सफलता के साथ देश भर में प्रसिद्धि हासिल की और पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए। सुपरस्टार अब नितेश तिवारी की रामायण सहित कई बड़ी आगामी रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिसमें वह रावण की शक्तिशाली भूमिका में नज़र आएंगे। उनके पास एक और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन–अप्स भी है, जो उन्हें सबसे रोमांचक अखिल भारतीय सितारों में से एक के रूप में और भी मज़बूत करता है।

नयनतारा:- नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ 2023 की सबसे बड़ी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान में अभिनय किया और जल्द ही सबसे पसंदीदा अखिल भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। अब उनके पास फिल्मों की एक रोमांचक लाइनअप है, जिसमें टॉक्सिक– अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन–अप्स और कई अन्य बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट शामिल हैं।

फिल्मों का नेतृत्व भारत के सबसे बड़े सितारों ने किया है, जिन्होंने अखिल भारतीय सनसनी के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। वे न केवल एक निश्चित क्षेत्र या इलाके में दिल जीत रहे हैं, बल्कि देशभर के सिनेमाघरों, फिल्मों और दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वे अब अखिल भारतीय सनसनी के रूप में पहचाने जाते हैं, यह सब उनके आकर्षक अभिनय, अविश्वसनीय स्क्रीन उपस्थिति, कड़ी मेहनत और उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की बदौलत है। उन्होंने न केवल दक्षिण में बल्कि पूरे देश और उसके बाहर भी बड़े पैमाने पर फैंस बनाए हैं। रश्मिका मंदाना से लेकर प्रभास और अन्य तक, यहां भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय सनसनी हैं जो सिनेमाघरों और सभी के दिलों पर राज कर रही हैं।

रश्मिका मंदाना, जिन्होंने कुछ साल पहले ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था। बहुत कम समय में तमिल और तेलुगु फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा डियर कॉमरेड, एनिमल, पुष्पा फ्रैंचाइज़ी, छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं।

मोबाइल की लत कर रही रिश्ते तबाह वक्त रहते संभल जाने में है भलाई

एकता

फोन हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या ये आपके पार्टनर से भी ज्यादा जरूरी है? दिनभर ऑफिस में 8 घंटे से ज्यादा काम, फिर सफर में 2 घंटे फोन हाथ में और घर आने के बाद भी फोन से नजरें नहीं हटतीं, क्या ये ठीक है? फोन इस्तेमाल करना गलत नहीं है। लेकिन जब वही वक्त आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, तब फोन में उलझना गलत साबित हो सकता है। ये आदत धीरे-धीरे आपके रिश्ते को कमजोर कर देती है।

शायद आपने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं होगा। लेकिन अब सोचना चाहिए। जो लोग नौकरी या बिजनेस करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका वैसे भी कम मिलता है। अगर वो भी फोन स्क्रॉल करते हुए निकल जाए, तो सामने वाले को बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत या अहमियत नहीं समझते। इससे प्यार और नजदीकी पर असर पड़ता है। कोई भी इंसान ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। खासकर तब, जब एक-दूसरे के साथ वक्त बिताने का समय बहुत कम हो। तो फिर सवाल है, आप इसे कैसे बदल सकते हैं?

कपल थेरेपिस्ट वैनेसा मारिन ने इस बारे में एक रील शेयर की। उन्होंने बताया कि फोन की ये आदत कपल्स के बीच झगड़ों का बड़ा कारण बन रही है। ये सिर्फ ज्यादा स्क्रीन टाइम की बात नहीं है। इससे ये मैसेज भी जाता है कि आप अपने पार्टनर को नजरअंदाज कर रहे हैं। लगातार स्क्रॉल करने से साथी को अकेला, दूर और कम अहमियत वाला महसूस होता है।

इसका हल क्या है?

इस समस्या का हल निकालने के लिए वह सलाह देती हैं कि फोन के इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं तय करें। जैसे, खाना खाते समय फोन को एक तरफ रख दें, पार्टनर के साथ टहलने जाएं तो फोन घर पर छोड़ दें, और सोने से पहले फोन का इस्तेमाल न करें। साथ ही, फोन को बेडरूम के बाहर रखना भी एक अच्छा तरीका है। सबसे अहम बात जो उन्होंने जोड़ी, वह यह कि अगर आपका साथी किसी गंभीर विषय पर बात कर रहा है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपना फोन नीचे रखकर उनकी बात ध्यान से सुनें ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं और उनकी परवाह करते हैं।

'क्या बनाएं' की झंझट ख़त्म!

उबले राजमा से दो हेल्दी और टेस्टी डिशेज़ मिनटों में तैयार

दिव्यांशी भदौरिया

हर घर में रोज की कहानी है कि आज खाने में क्या बनाएं। दिनभर महिलाएं सोचती रहती हैं बच्चों और बड़ों के लिए ऐसा क्या बनाएं जो खाने में टेस्टी और हेल्दी जरुर है। अब आप यह चिंता छोड़ दीजिए। बस उबले राजमा से ये 2 डिशेज को जरुर बनाएं, इसे बनाना भी काफी आसान है। आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स टाइम के लिए बना सकते हैं। वैसे तो राजमा खाना सेहत के लिए हेल्दी माना गया है। राजना के माध्यम से आप कई सारी टेस्टी डिशेज बना सकती हैं। आज हम आपको उबले हुए राजमा से चाट और कटनेट दोनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो बेहद ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। नोट करे इन दोनों डिशेज की आसान विधि।

उबले हुए राजमा की चाट

सामग्री

- नींबू का रस–1–2 बड़े चम्मच
- चाट मसाला–1/2 चम्मच
- काला नमक–1/4 चम्मच
- तेल – 1 बड़ा चम्मच
- उबले हुए राजमा–2 कप
- प्याज कटी हुई–1/2 कप
- टमाटर कटे हुए–1/2 कप
- हरी मिर्च बारीक कटी हुई–1–2
- धनिया पत्ती छोटे–छोटे आकार में–1/4 कप

उबले राजमा की चाट बनाने की विधि:- इसके लिए आप उबले हुए राजमा को बड़े बाउल में डाल लें। अब इसमें सभी सब्जियों को डालना है, जैसे कि–कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती आदि मिला लीजिए। इस मिश्रण में नींबू का रस, चाट मसाला और काला नमक मिलाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद एक पैन में तेल को गर्म करें और अब इसमें राजमा का मिश्रण डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएं और फिर आप इसे गरमा गरण परोसें। तैयार है आपकी राजमा चाट।

राजमा कटलेट

सामग्री

- उबले हुए राजमा–2 कप
- ब्रेड क्रम्ब्स–1/2 कप
- प्याज कटी हुई–1/2 कप
- टमाटर कटे हुए–1/2 कप
- हरी मिर्च बारीक कटी हुई– 1–2
- धनिया पत्ती छोटे–छोटे आकार में–1/4 कप
- अदरक–लहसुन का पेस्ट–1 चम्मच
- नमक–स्वादानुसार
- तेल–तलने के लिए

उबले राजमा की चाट बनाने की विधि:-राजमा कटलेट कैसे बनाएं? इसे बनाने के लिए पहले आप उबले हुए राजमा को मिक्स करें। एक पैन लें और इसमें तेल डाल दीजिए। अब इसमें बारिक कटी हुई सब्जियां जैसे–प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालें। साथ में अदरक–लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद स्वादानुसार नमक डालें। अब उबले हुए राजमा के बने मिश्रण में डालें और अच्छे से मिक्स (मैश) कर लें। इसके बाद आप छोटे–छोटे कटलेट बनाएं। फिर कटलेट को ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटें और गर्म तेल में फ्राई कर लें। सुनहरा होने के बाद इसे फ्राई करें। इसके बाद आप हरी चटनी के साथ गरमा–गरम सर्व करें।

आपकी सिंपल कुर्ती में चार चांद लगाएंगी ये लेटेस्ट सलवार डिज़ाइन हर कोई करेगा तारीफ़

अनन्या मिश्रा

हर लड़की को सलवार-सूट पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है। सलवार सूट कैरी करने के बाद आपकी लुक ट्रेडिशनल नजर आता है। वैसे तो मार्केट में कई तरह के डिफरेंट सूट मिल रहे हैं। जिनको आप अपनी पसंद के हिसाब से पहन सकती हैं। यह एक ऐसा पहनावा है, जिसको आप कॉलेज, ऑफिस या वेडिंग फंक्शन कहीं भी पहनकर जा सकती हैं। आजकल महिलाएं भी साड़ी की जगह सूट पहनना अधिक पसंद करती हैं। कुर्ती के संग बॉटम में कोई लैगी तो कुछ पटियाला सलवार तो कोई नॉर्मल सलवार पहनता है।

आजकल मार्केट में कई तरह की डिजाइनर सलवार मिलती हैं। जिनको आप अपनी सिंपल कुर्ती के साथ पहनकर अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रेडीमेड यह सलवार खरीद सकती हैं। इसमें आपको फ्री साइज मिलता है। यह सलवार हर बॉडी टाइप पर फिट बैठती है। ऐसे में अगर आप भी सिंपल कुर्ती में अपने लुक को कंफर्टेबल और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल वाली सलवार दिखाने जा रहे हैं, जिनको कैरी करके आप अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं।

पोंचू सलवारः- आजकल पोंचू सलवार पैटर्न काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस सलवार का बॉटम नीचे से कम फैला होता है। आप इसको आसानी से पहनकर चल सकती हैं। पोंचू सलवार कैरी करने में भी काफी आरामदायक होती है। हालांकि इस सलवार का पूरा लुक प्लेन होता है और नीचे की तरफ कोई लेस का बॉर्डर लगवा सकती हैं। इस तरह से आपका लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है। इस सलवार को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगहों से खरीद सकती हैं। पोंचू सलवार आपको 250 से 400 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ आप मोजड़ी जूती कैरी कर सकती हैं।

चुन्नटदार एम्ब्रायडरी सलवारः- अगर आपको प्लेन कुर्ती के साथ अपने लुक को गॉर्जियस बनाना है, तो इसके लिए आप चुन्नटदार एम्ब्रॉडरी वाली सलवार जरूर खरीदें। आजकल यह सलवार काफी ज्यादा डिमांड में है। इस सलवार का नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा संकरा होता है। अगर आप इस सलवार को शॉर्ट कुर्ती के साथ कैरी करती हैं, तो इससे आपका लुक क्लासी नजर आता है। इस तरह की चुन्नटदार एम्ब्रॉयडरी सलवार यंग गर्ल्स के लिए पहली पसंद होती है। ऑनलाइन में यह सलवार आपको 300 से 500 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके साथ आप हाई हील्स फुटवियर कैरी कर सकती हैं।

थ्रेड वर्क सलवारः- अगर आपको अपना लुक एलिगेंट रखना है, आप किसी भी सिंपल कुर्ती को कंट्रास्ट कलर की थ्रेड वर्क सलवार संग कैरी कर सकती हैं। यह सलवार आपको ब्यूटीफुल लुक देती है। इस सलवार का घेर एकदम नॉर्मल होता है और यह अधिकतर आपको कॉटन फैब्रिक में मिलती है। इस पर थ्रेड के साथ मिरर का भी वर्क होता है। ऐसे में इस सलवार का लुक काफी ज्यादा प्यारा लगता है। ऑनलाइन में यह सलवार 200 से 450 रुपए की कीमत में मिल जाएगा। आप इसके साथ राजस्थानी बीड्स वाली फ्लैट फुटवियर कैरी कर सकती हैं।

साउथ इंडिया के ज़बरदस्त हैं ये ब्यूटी हैक्स चेहरे की रंगत में आएगा निखार

सूफिया सैय्यद

नेचुरल तरीके से स्किन को ग्लोइंग बनाना सबसे आसान तरीका होता है। अब चाहे नॉर्थ हो या फिर साउथ हर जगह स्किन को चमकदार बनाने के लिए ब्यूटी हैक्स को जरुर अपनाते हैं। खासकर साउथ की महिलाएं अपने बालों से लेकर स्किन का खासा ध्यान रखती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में शादी–विवाह के मौके पर खास तरह का उबटन लगाया जाता है। जो स्किन के लिए काफी गुणकारी होता है। यह हल्दी, चंदन और बेसन को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह ब्यूटी रिचुअल्स वहां लंबे समय से चली आ रही है। आप भी इन ब्यूटी हैक्स के जरिए अपनी स्किन में निखार ला सकती हैं।

नारियल का तेल

सबसे ज्यादा नारियल साउथ में ही पाया जाता है। नारियल का तेल साउथ में खाने–पीने से लेकर स्किन और बालों की देखभाल की जाती है। आप हल्के गुनगुने नारियल तेल से मालिश करें यह आपके ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ता है।

हल्दी से बना फेस पैक

साउथ इंडिया में मसालें की आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। हल्दी से बना हुए फेस पैक लगाने से स्किन को सॉफ्ट और एक्ने भागा देता है। इसके साथ ही ब्राइट बनाने में भी काफी हेल्प करता है। क्योंकि हल्दी में एंटी– बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण होते हैं।

फेयरनेस सीरम

दक्षिण भारत में सेब, अनार और संतरे के छिलके को एलोवेरा जेल में मिलाकर सीरम तैयार कर लें। इसमें बादाम का तेल भी यूज किया जाता है। इन सब का पेस्ट बनाकर नारियल के तेल में पकाकर सीरम तैयार होता है। यह स्किन को ब्राइट बनाने में काम करता है।

करी पत्ता का यूज़ करें

करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। इसमें प्रोटीन और बीटा कैरोटिन होता है, जो हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। करी पत्ते को नारियल के तेल में उबालकर बालों में लगाने से सफेद बाल की समस्या और बालों के पतलेपान से छुटकारा मिल जाता है।

OMAXE
Turning dreams into reality
www.omaxe.com

UP RERA REGN. NO.: **UPRERAPRJ537348/04/2025**
RERA Website: www.up-rera.in
RERA COLLECTION BANK ACCOUNT NUMBER- 57500001725191
PROJECT LAUNCH DATE- 1ST MAY 2025

CHOOSE THE LIFESTYLE THAT MAKES A ROYAL STATEMENT

LAUNCHING

REGENT

AT GOMTI NAGAR EXT. LUCKNOW

LUXURIOUS 4 BHK HOMES

PRICES START FROM ₹2.35 CRORE*

T&C Apply

Artistic Impression

Designed to captivate everyone with its elegance, **"Regent"** our upcoming project at Grand Omaxe, Lucknow is meant to perpetuate the legacy of grand lifestyles. To add to the feel of sheer luxury, the serene environment and state-of-the-art amenities come together beautifully and make a royal statement.

SEAMLESS CONNECTIVITY

1.5 KMS	2.5 KMS	5.9 KMS	6.4 KMS
MOTHER AND CHILD CARE HOSPITAL	PHOENIX PALASSIO MALL	DELHI PUBLIC SCHOOL	GOMTI NAGAR

GRAND AMENITIES OF TOWNSHIP

- JOGGING TRACK
- SWIMMING POOL
- BANQUET HALL
- EXCLUSIVE PLAY AREA FOR KIDS
- BILLIARDS, SNOOKER & POOL TABLES

PROJECT NAME: GH-1 GRAND OMAXE REGENT | **PROJECT PROMOTED BY:** OMAXE LIMITED | **CIN:** L74899HR1989PLC051918
CO-PROMOTED BY: ADVAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED | **CIN:** U45202PB2006PTC030172

REGISTERED OFFICE: SHOP NO. 19B, FIRST FLOOR, OMAXE CELEBRATION MALL, SOHNA ROAD, GURUGRAM, HARYANA - 122001. | **CORPORATE OFFICE:** 10, L.S.C., KALKAJI, NEW DELHI - 110019. **Website: www.omaxe.com**
SITE OFFICE: WORLD OF OMAXE, SECTOR 7, GOMTI NAGAR EXTENSION, AMAR SHAHEED PATH, LUCKNOW (U.P.) - 226002. | **ZONAL OFFICE:** 2ND FLOOR, CYBER TOWER, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226010

Disclaimer: This Advertisement is indicative in nature & does not constitute as an offer or invitation for the purpose of Registration/Booking/Sale. Visual representations shown in this advertisement are purely conceptual and not a legal offering etc. The viewer /prospective buyer may seek all such information, sanction plans, approvals, development schedule, specifications, facilities & amenities, from the company in respect of the concerned project/ phase that he/she may be interested in, before any such booking/ registration, etc. Further details of the projects)/phase are available at the company/site/marketing office(s) and/or company website and on the website of RERA, UP: www.up-rera.in and/or at their office.

CALL FOR MORE DETAILS
9999 999 804

शिक्षा में नवाचार
प्रगति का आधार

बेसिक शिक्षा : विजन@2047

अवस्थापना कार्य

- प्रत्येक न्याय पंचायत में मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय की स्थापना (सर्वोत्तम श्रेणी की सुविधाएं, अत्याधुनिक कक्षाएं, डिजिटल उपकरण)
- 'करो और सीखो' सिद्धांत के आधार पर कौशल केंद्रों की स्थापना (नवाचार, समस्या समाधान, रचनात्मकता, सहयोग एवं डिजिटल साक्षरता)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मजबूत नींव एवं अंतर्राष्ट्रीय लर्निंग आउटकम

कक्षा-3 तक 100% आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता, कक्षा-8 तक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेड-स्तरीय अधिगम

शिक्षक गुणवत्ता एवं नवाचार

सतत प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं नवाचार के लिए सक्षम बनाना, संकुल स्तर पर 100 शिक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यशाला हेतु बहुउद्देश्यीय हॉल

प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर पर काउंसलर की नियुक्ति

लर्निंग बाय डूइंग

उच्च प्राथमिक शिक्षा में 'करो और सीखो' पद्धति को पूरी तरह से लागू करना

छात्रों में व्यावहारिक कौशल के साथ ही रचनात्मक सोच का विकास करना

उत्तर प्रदेश को देश की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी राज्य के रूप में मॉडल बनाना

प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% एवं ट्रांजिशन रेट 100% प्राप्त करना

छात्र-छात्राओं का ड्रॉप आउट पूरी तरह समाप्त करना

कस्तूरबा बालिका विद्यालय

- सभी छात्राओं को प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, नवाचार, खेलकूद, स्टार्टअप एवं अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने हेतु दक्ष/निपुण बनाना
- सभी छात्राओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाना, ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं आत्मविश्वास के साथ सशक्तीकरण करना
- कम से कम 200 बालिकाओं को राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं एवं 25 छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना
- कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को स्किल हब के रुप में विकसित किया जाना, जिससे छात्राओं को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

बुनियादी ढांचा एवं शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं निगरानी, व्यक्तिगत शिक्षा एवं नवाचार हेतु प्रमुख गतिविधियां बाल वाटिका की स्थापना, शिक्षक भर्ती एवं प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण, निगरानी प्रणाली की स्थापना, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, नवाचार एवं तकनीकी निगरानी आदि

माध्यमिक शिक्षा : विजन @2047

- व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा
- SDG-4 के अनुरूप समता आधारित शिक्षा
- असेवित बस्तियों का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुरूप अवस्थापना सुविधाएं
- रोबोटिक्स, एआई एवं वीआर की प्रयोगशालाएं
- प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल पुस्तकालय नेटवर्क
- स्कूली खेलों हेतु अंतरराष्ट्रीय सुविधा का विकास

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश